

सदन की मर्यादा और परंपराओं को बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी: ओम बिरला

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बुधवार को ध्वनिमत से खारिज होने के बाद गुरुवार को अध्यक्ष के आसन पर बैठे बिरला ने कहा कि भारत के संसदीय इतिहास में तीसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर संकल्प आया और इस पर दो दिनों तक 12 घंटे से अधिक चर्चा हुई। उनका हमेशा प्रयास रहा है कि सदन के भीतर प्रत्येक सदस्य नियमों और प्रक्रियाओं के तहत अपने विचार व्यक्त कर सके और सभी को पर्याप्त अवसर मिले।

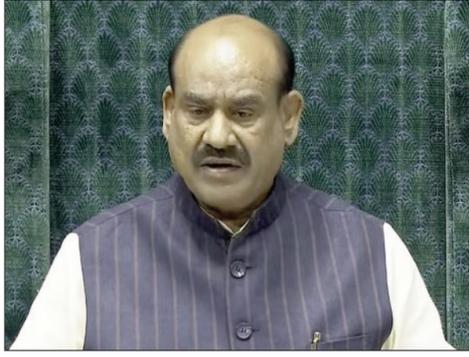
बिरला ने कहा कि यह सदन समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की आवाज बने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष के निर्वाचन का प्रावधान है

और इस पावन सदन ने उन्हें दूसरी बार अध्यक्ष पद का दायित्व दिया। उनका प्रयास रहा है कि सदन की कार्यवाही निष्पक्षता, अनुशासन और संतुलन के साथ संचालित हो। दस फरवरी को विपक्ष के कुछ सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था और उन्होंने अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण के साथ ही सदन की कार्यवाही से स्वयं को अलग कर लिया था।

उन्होंने कहा कि इस चर्चा के दौरान अनेक विचार, दृष्टिकोण और भावनाएं सामने आईं और उन्होंने सभी को गंभीरता से सुना। उन्होंने सदन के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। बिरला ने स्पष्ट किया कि कुछ सदस्यों का मानना था कि प्रतिपक्ष के नेता सदन से ऊपर उठकर किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, लेकिन यह

किसी को विशेष अधिकार नहीं है। सदन नियमों से चलता है और ये नियम न सरकार ने बनाए हैं, न प्रतिपक्ष ने, बल्कि सदन ने बनाए हैं और सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू होते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री या मंत्रीगण भी यदि सदन में वक्तव्य देना चाहते हैं तो नियम 372 के तहत अध्यक्ष से अनुमति लेनी होती है। किसी सदस्य को नियमों से परे जाकर बोलने का विशेषाधिकार नहीं है। उन्होंने संसदीय परंपराओं का जिक्र करते हुए कहा कि 1957 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित कुछ फोटो सदन में रखने चाहे तो स्पीकर ने पहले उन्हें दिखाने का निर्देश दिया और अटल जी ने उसका सम्मान किया। उन्होंने 1958 में भी कई उदाहरण हैं जब बिना स्पीकर की अनुमति दस्तावेज सदन में



नहीं रखे गए।

बिरला ने कहा कि अध्यक्ष के निर्णय से कोई भी सदस्य सहमत या असहमत हो सकता है, लेकिन नियमों और परंपराओं को लागू करना उनका कर्तव्य है। जब भी

कुछ सदस्य सदन की मर्यादा के विरुद्ध आचरण करते हैं तो उन्हें कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 105 का हवाला देते हुए कहा कि संसद में बोलने की आजादी है,

लेकिन यह सदन द्वारा स्वीकृत नियमों और स्थाई आदेशों के अधीन है।

उन्होंने प्रतिपक्ष द्वारा माइक बंद करने के आरोपों पर कहा कि आसन के पास कभी भी माइक ऑन-ऑफ करने का बटन नहीं होता। जिस सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाती है, उसी का माइक ऑन होता है। उन्होंने महिला सदस्यों के सम्मान का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा महिला सांसदों को बोलने का पर्याप्त अवसर दिया और प्राथमिकता दी, लेकिन जब कुछ महिला सदस्य वेल पार कर ट्रेजरी बेंच की तरफ जाकर नारेबाजी कर रही थीं और बैनर दिखा रही थीं, तो अप्रत्याशित स्थिति बन सकती थी। इसलिए उन्होंने सदन की व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री को बोलने से रोका।

बिरला ने कहा कि उनका प्रयास

हमेशा रहा है कि किसी सदस्य का निर्लेखन न हो, लेकिन सदन की व्यवस्था बनाए रखना भी उनकी जिम्मेदारी है। जब कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं तो उनका मन दुखी होता है, लेकिन यह सोचना होगा कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि 1997 और 2001 में भी सदन की मर्यादा और गरिमा पर चर्चा हुई थी और सर्वसम्मति से संकल्प लिया गया था कि नारेबाजी, पोस्टर दिखाना, कागज फाड़ना और अभद्र मुद्राओं का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उस समय सोनिया गांधी ने भी कहा था कि वेल में आने पर पूर्ण रोक लगनी चाहिए और उल्लंघन पर स्वतः अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। सदन की मर्यादा और परंपराएं बनाए रखना जरूरी है क्योंकि सदन का आचरण पूरे देश में लोकतांत्रिक

संस्थाओं के लिए उदाहरण होता है। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है।

बिरला ने कहा कि उन्हें अच्छा नहीं लगता कि बार-बार कहना पड़े कि तखियां दिखाना, नारे लगाना, कागज फाड़ना और मेजों पर चढ़ना संसदीय लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। सदन और देश इस मत से सहमत नहीं है। उन्होंने आग्रह किया कि सदन में अच्छी परंपराओं और मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए सामूहिक संकल्प लिया जाए और सामूहिक विचार-विमर्श हो। सदन को देखकर देश का विश्वास और भरोसा कायम रहता है और लाखों लोग अपेक्षा करते हैं। इसलिए हमें सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए।

इन्फोसिस मोहाली में 2700 युवाओं को सीधे रोजगार और हजारों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देगी: भगवंत सिंह मान

मार्च 2022 से अब तक पंजाब में 1.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे 5.44 लाख युवाओं के लिए नौकरियाँ पैदा हो रही हैं

यज्ञांश शर्मा

मोहाली

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि पंजाब अपनी औद्योगिक प्रगति में एक निर्णायक परिवर्तन देख रहा है। 2022 से पहले की लूट-खसोट और अस्थिर माहौल के बाद अब वैश्विक निवेशक राज्य में फिर से लौट रहे हैं। मोहाली में इन्फोसिस के 286 करोड़ रुपये की लागत वाले नए कैम्पस के शिलान्यास समारोह के बाद बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना 2,700 युवाओं को सीधे रोजगार देगी, जबकि हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मार्च 2022 से अब तक पंजाब सरकार को 1.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिसने 5.44 लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। उन्होंने आगे कहा कि मोहाली में 13 से 15 मार्च तक आयोजित होने वाला प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन राज्य की औद्योगिक प्रगति के लिए एक ऐतिहासिक अवसर साबित होगा और



आने वाले तीन दिन पंजाब के आर्थिक विकास की नई कहानी लिखेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विश्व-प्रसिद्ध कंपनी इन्फोसिस के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार की उद्योग-पक्षीय नीतियों में विश्वास व्यक्त करने के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने देश की आर्थिक प्रगति में इन्फोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति के महान योगदान को भी याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा, आज पंजाब के लिए, विशेषकर औद्योगिक

क्षेत्र के लिए, ऐतिहासिक दिन है। मैं वैश्विक कंपनी इन्फोसिस के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और हमारी सरकार की उद्योग-पक्षीय नीतियों पर विश्वास जताने के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं देश की आर्थिक प्रगति में इन्फोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति के अमूल्य योगदान को भी याद करता हूँ। भारतीय आईटी क्षेत्र के अग्रदूत माने जाने वाले नारायण मूर्ति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें

भारतीय आईटी उद्योग का पितामह कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इन्फोसिस की 286 करोड़ रुपये की इस नई परियोजना का शिलान्यास मोहाली में किया जा रहा है, जो 2,700 युवाओं को सीधे रोजगार देगी और हजारों युवाओं के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना के पहले चरण में एक एकीकृत कैम्पस स्थापित किया जाएगा, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक, फूड कोर्ट और अन्य आधुनिक सुविधाएँ होंगी। लगभग 3.50

लाख वर्ग फुट क्षेत्र में बनने वाले इस कैम्पस में लगभग 3,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इस परियोजना के लिए इन्फोसिस को पूरा सहयोग देगी ताकि अन्य कंपनियों भी पंजाब में निवेश करने के लिए प्रेरित हों और युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा हों। इन्फोसिस की वैश्विक प्रतिष्ठा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कंपनी तकनीक और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है और वर्तमान में इसके लगभग 3,37,034 कर्मचारी दुनिया भर में कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले नौ महीनों में कंपनी ने 15.12 अरब डॉलर की आय दर्ज की है। उन्होंने कहा कि इससे पंजाब अब वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर उभरकर सामने आया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 20 मार्च को लुधियाना में 3,200 करोड़ रुपये के निवेश से बनने वाले देश के दूसरे सबसे बड़े टाटा स्टील प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा। यह परियोजना 2,500 युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी और राज्य के आर्थिक विकास को गति देगी।

2047 के विकसित भारत में हरियाणा की रहेगी अग्रणी भूमिका: नायब सैनी

भूपेंद्र शर्मा

चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2047 के विकसित भारत में हरियाणा की अग्रणी भूमिका रहेगी। इसके लिए हरियाणा निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने विकसित भारत का लक्ष्य देने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री गुरुवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक समिट में बोल रहे थे।

इस दौरान संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसान, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार और गरीब उत्थान के चार स्तंभों पर काम करने के आह्वान किया है। हरियाणा सरकार इन सभी पर तेजी से कार्य कर रही है। आज हरियाणा का किसान पारंपरिक खेती के साथ-साथ प्राकृतिक खेती, बागवानी में बेहतर कार्य कर रही है। हरियाणा सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आज महिलाएं कृषि, हेल्थ, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भरपूर योगदान दे रही हैं। प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए स्टार्ट-अप नीति बनाई है। गरीब उत्थान के लिए मजबूती से कार्य किया जा रहा है। आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, पीएम जनधन खाता योजना, किसान सम्मान निधि जैसी



योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने पंचर डिपार्टमेंट बनाया है। इसका मकसद है कि आने वाले समय में लंबे समय को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाएं ताकि लोगों को कोई परेशानी न आए। हर क्षेत्र में व्यवस्थित विकास सुनिश्चित हो सके। इसी सोच के साथ हरियाणा सरकार

विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवाओं को शोध के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि विश्वविद्यालयों के छात्र विभिन्न क्षेत्रों में शोध कर सकें और यह पहचान सकें कि किन-किन क्षेत्रों में क्या समस्याएँ हैं। इसके साथ-साथ इन्फोसिस समानान्तर भी निकाल सकें। इसी दृष्टि से एक विशेष विभाग फ्यूचर डिपार्टमेंट स्थापित किया गया है, जो भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं पर काम करेगा।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में भारत एआई, अनुसंधान और विकास को अपना रहा है। प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि नई तकनीकों का अधिकतम उपयोग आम जनता के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। हाल ही में आयोजित एआई समिट में भी दुनिया भर से विशेषज्ञ और प्रतिनिधि भारत आए और उन्होंने तकनीक के भविष्य को लेकर अपने विचार साझा किए। इसी दिशा में हरियाणा सरकार भी आगे बढ़ रही है। पिछले बजट में यह घोषणा की गई थी कि पंचकुला और गुरुग्राम में दो स्थानों पर एआई हब स्थापित किए जाएंगे। इस दिशा में कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में चंडीगढ़ में भी एक एआई समिट आयोजित की गई, जिसमें इस क्षेत्र से जुड़े अनेक विशेषज्ञों और प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ईरान समस्या सुलझेगी तब भी गैस संकट खत्म नहीं होगा: राहुल गांधी

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध से उत्पन्न गैस सिलेंडर संकट पर कहा कि यदि ईरान के स्तर पर समस्या सुलझ भी जाती है, तब भी यह संकट समाप्त नहीं होगा, क्योंकि दुनिया बदल रही है और संरचना बदल रही है। इसलिए हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा। यदि भारत को केंद्र में रखकर काम नहीं किया गया तो समस्या और गहरी होगी।



और तेल संकट की अभी शुरुआत है। उन्होंने सदन में बोलने की इच्छा जताई, लेकिन नई प्रक्रिया के चलते उन्हें अवसर नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अब मंत्री पहले तय करेंगे, फिर वह

बोलेंगे और उसके बाद मंत्री जवाब देंगे। असलमुद्दा यह है कि गैस, पेट्रोल और सभी ईंधन समस्या बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता हो चुका है। उन्होंने कहा कि अभी तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास समर्थ है। प्रधानमंत्री और सरकार को तुरंत इस संकट से निकलने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। अगर तैयारी नहीं की गई तो करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। यह मुद्दा केवल ईरान से कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम एक अस्थिर समय में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे समय में पुराना सोच

काम नहीं करेगा और हमें नई सोच अपनानी होगी। उन्होंने कहा कि वह कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक बड़ी समस्या को सामने देख रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के लोग सुरक्षित रहें और ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह खुद घबराए हुए हैं। इस वजह से सदन में नहीं आ पा रहे हैं। प्रधानमंत्री देश से कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, जबकि वह खुद अलग कारणों से घबराए हुए हैं।

ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत में जयशंकर ने ऊर्जा सुरक्षा का भी उठाया मुद्दा

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के हालात के बीच ईरान के विदेश मंत्री से अब तक तीन बार बातचीत की। इसमें भारतीय जहाजों की सुरक्षा और देश की ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा हुई।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को साप्ताहिक पत्रकार वार्ता में एक सवाल पर कहा, पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच तीन बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े

मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।

उल्लेखनीय है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सबसे ज्यादा तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसके चलते देश में गैस की उपलब्धता में कमी आई है।

वहीं बांग्लादेश को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पर प्रवक्ता ने कहा कि भारत विशेष रूप से हमारे पड़ोसियों के लिए परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक है। हमें बांग्लादेश सरकार से डीजल की आपूर्ति के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिस पर



विचार किया जा रहा है। बांग्लादेश के साथ संबंधों के प्रति हमारे जनकेंद्रित और विकास-उन्मुख दृष्टिकोण को देखते हुए हम 2007 से मुमालीगढ़ रिफाइनरी से विभिन्न माध्यमों: जलमार्ग, रेल और बाद

में भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइप-लाइन के माध्यम से डीजल की आपूर्ति कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2017 में मुमालीगढ़ रिफाइनरी और बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के बीच प्रारंभिक रूप से सहमत शर्तों पर हाई-स्पीड डीजल की आपूर्ति के लिए एक बिक्री-खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि 2007 से बांग्लादेश को डीजल का निर्यात काफी हद तक जारी रहा है, लेकिन निर्यात लेते समय भारत की रिफाइनरी क्षमता, अपनी आवश्यकता और डीजल की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाएगा।

कृषि नीति और नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी बहुत जरूरी: राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने कहा कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें नीति निर्माण, निर्णय-निर्धारण तथा नेतृत्व पदों में अधिक अवसर मिलना चाहिए। महिलाओं की व्यापक भागीदारी से कृषि क्षेत्र में भी लैंगिक समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

राष्ट्रपति गुरुवार को यहां ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन द रोल ऑफ वीमैन इन एग्री-फूड सिस्टम्स (जीसीडीब्ल्यूएस-2026) के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाएं बुवाई, कटाई, प्रसंस्करण और फसलों को बाजार तक पहुंचाने सहित कृषि की लगभग हर गतिविधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा वे मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, वन उत्पादों के उपयोग और कृषि आधारित उद्यमों के संचालन में भी लगातार योगदान दे रही हैं। महिलाएं कृषि

अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अमूल्य योगदान देती हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में कुल छात्रों में 50 प्रतिशत और अन्य विश्वविद्यालयों में 60 प्रतिशत से अधिक छात्राएं हैं, जो शैक्षणिक प्रदर्शन में भी उत्कृष्ट हैं। ऐसे में सरकार, समाज और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों की जिम्मेदारी है कि इन प्रतिभाशाली छात्राओं को प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान किया जाए, ताकि वे कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में नेतृत्व कर सकें।

राष्ट्रपति ने कहा कि मातृत्व में नेतृत्व की भावना निहित होती है, लेकिन अक्सर इसे घर की सीमाओं तक ही सीमित मान लिया जाता है। इस सोच को बदलते हुए महिलाओं को कृषि क्षेत्र में नेतृत्व देने के लिए आगे बढ़ना होगा। उन्होंने बताया कि संयुक्त



राष्ट्र ने वर्ष 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमन फार्मर घोषित किया है। इसका उद्देश्य



कृषि-खाद्य मूल्य श्रृंखला में लैंगिक अंतर को कम करना और महिलाओं की नेतृत्व भूमिका को बढ़ावा देना है।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय कृषि संसाधनों और अन्य सहयोगी व्यवस्थाओं से जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि पिछले दशक में भारत ने महिलाओं को कृषि क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए कई पहल की हैं। महिला-नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने वाली पहलें इस दिशा में प्रभावी साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस और पार्टनरशिप को समान महत्व देने पर सहमति बनी है। पीपल के आयाम में लैंगिक समानता को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कृषि सहित सभी क्षेत्रों में प्रभावी लैंगिक समावेशन से न केवल सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, बल्कि पृथ्वी को भी अधिक संवेदनशील और सामंजस्यपूर्ण बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस और पार्टनरशिप को समान महत्व देने पर सहमति बनी है। पीपल के आयाम में लैंगिक समानता को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कृषि सहित सभी क्षेत्रों में प्रभावी लैंगिक समावेशन से न केवल सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, बल्कि पृथ्वी को भी अधिक संवेदनशील और सामंजस्यपूर्ण बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस और पार्टनरशिप को समान महत्व देने पर सहमति बनी है। पीपल के आयाम में लैंगिक समानता को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कृषि सहित सभी क्षेत्रों में प्रभावी लैंगिक समावेशन से न केवल सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, बल्कि पृथ्वी को भी अधिक संवेदनशील और सामंजस्यपूर्ण बनाया जा सकेगा।

थर्ड फ्रंट में जिसे जाना वह जाए, हमारी सरकार प्रदेश में करती रहेगी जनहित कार्य : सुक्खू

मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध करवाई गई

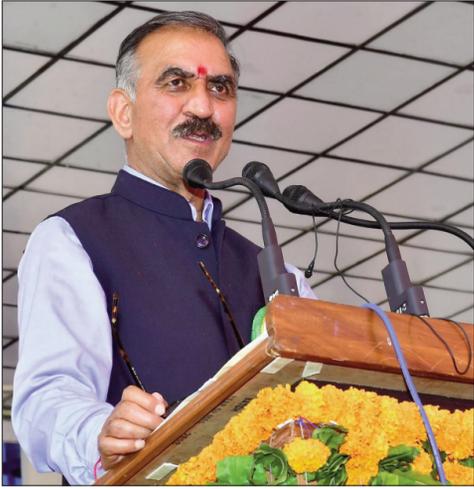
एजेंसी (हि.स.)
हमीरपुर

मुख्यमंत्री सुखचंद्र सिंह सुक्खू वीरवार को दो दिवसीय दौरे पर हमीरपुर जिला के नादौन क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान अमतर क्रिकेट स्टेडियम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नादौन डिग्री कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने बहुउद्देशीय भवन का शिलान्यास किया तथा डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल क्लासरूम और स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर एनसीसी के डेट्टेड्स ने मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने थर्ड फ्रंट के सवाल पर कहा कि किसी को भी नहीं पार्टी बनाने का लोकतांत्रिक अधिकार है। जो व्यक्ति जाना चाहता है, वह जा सकता है और किसी को रोकना नहीं जा सकता।

दो दिवसीय दौरे पर हमीरपुर जिला के नादौन क्षेत्र पहुंचे सीएम

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार अपना दो वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हिमाचल के विकास की विरोधी बलों है और राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) के मुद्दे पर भाजपा ने चुपी ब्यों साध रखी है। नेता प्रतिपक्ष द्वारा रोबोटिक सर्जरी को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स की तर्ज पर हिमाचल में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जबकि उनके कार्यकाल में नैरचोक मेडिकल कॉलेज में एक एमआरआई मशीन तक स्थापित नहीं हो पाई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा और पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल के



विकास को लेकर कुंठाग्रस्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार

रही है, ताकि आम जनता को बेहतर इलाज मिल सके। एलपीजी गैस की उपलब्धता पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिलहाल गैस की कोई किल्लत नहीं है। यदि किसी प्रकार की कमी होती है तो सरकार हर संभव कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने नादौन डिग्री कॉलेज में अपने देर से पहुंचने के बावजूद छात्रों द्वारा इंतजार करने पर उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा में आधुनिकता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में कॉलेज में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और बहुउद्देशीय भवन की शुरुआत की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि जून माह से मेडिकल कॉलेज में कक्षाएं शुरू की जाएंगी और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में मल्टी सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके साथ ही डेंटल कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

75 वें वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता की

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रदेश के सबसे पुराने राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी के 75वें वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों सहित विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया और उनके उज्वल भविष्य की कामना की। रोहित ठाकुर ने कहा कि वार्षिक समारोह किसी भी छात्र के जीवन का अहम पड़ाव होता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार शिक्षा आधारित एवं रोजगार परक शिक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रदेश सरकार ने सभी राजकीय महाविद्यालयों में रैंकिंग व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे विभिन्न कॉलेजों के मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू होगी और विद्यार्थियों के सर्वांगीण



विकास में भी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि अभी तक राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नेक) के अंतर्गत प्रदेश के केवल 34 कॉलेज ही आते हैं और शिक्षा विभाग की रैंकिंग प्रणाली में सभी 134 कॉलेजों को शामिल किया जाएगा। इसकी शुरुआत इसी माह से करने की तैयारियां विभाग द्वारा कर ली गई हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए आधारभूत ढांचे के सुदृढीकरण के साथ ही प्राध्यापकों की नियुक्ति को भी प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में 484 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्तियां विभिन्न कॉलेजों में की हैं। इसके अतिरिक्त विभाग को 394 सहायक प्राध्यापकों के पद भरने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कॉलेज कैडर में पदोन्नति के माध्यम से प्राचार्य के लगभग 103 पद वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भरे गए हैं। इन्होंने प्रयासों का सुपरिणाम है कि उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन (दाखिले) अनुपात में आज हिमाचल देश भर में 43 प्रतिशत की दर के साथ दूसरे स्थान पर है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कुली स्तर पर भी शैक्षिक ढांचे को मजबूत करने के लिए दोस कदम उठाए जा रहे हैं।

जीजीएम साइंस कॉलेज की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित

एजेंसी (हि.स.)
जम्मू

जम्मू स्थित जीजीएम साइंस कॉलेज की एनएसएस यूनिट्स और उन्नत भारत अभियान समिति द्वारा मखनपुर गांव में नि-शुल्क मेडिकल हेल्थ चेक-अप कैम्प का आयोजन किया गया। यह शिविर हेक्सामेड डायग्नोस्टिक सेंटर, छन्नी हिममत के सहयोग से लगाया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीणों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। शिविर के लिए मेडिकल टीम और एनएसएस स्वयं सेवकों को कॉलेज परिसर से प्रिंसिपल प्रो. (डॉ.) रमेश कुमार गुप्ता ने वरिष्ठ संकाय सदस्यों की उपस्थिति में रवाना किया। उन्होंने इस पहल को सामुदायिक सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी के दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। शिविर से पहले एनएसएस स्वयंसेवकों और उन्नत भारत अभियान समिति के सदस्यों ने गांव में



घर-घर जाकर लोगों को कार्यक्रम की जानकारी दी और उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। शिविर के दौरान स्वयंसेवकों ने मरीजों के फंजीकरण और परामर्श प्रक्रिया में डॉक्टरों की सहायता कर कार्यक्रम को सुचारु रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हेक्सामेड डायग्नोस्टिक सेंटर के अनुभवों डॉक्टरों की टीम ने ग्रामीणों का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सहित अन्य आवश्यक जांचों की गईं। डॉक्टरों ने लोगों को संतुलित आहार, स्वस्थ जीवनशैली और नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व के बारे में भी जानकारी दी।

जम्मू के आर.एस क्षेत्र में रसोई गैस लेने के लिए लोगों की लंबी-लंबी कतारें

जम्मू। इंदरान-इजरायल-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब धीरे-धीरे भारत में भी देखने को मिल रहा है। जम्मू के आर.एस.पुरा क्षेत्र में गुरुवार सुबह रसोई गैस लेने के लिए लोगों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलीं। कई लोगों ने बताया कि गैस की बुकिंग करवाने के बावजूद उन्हें समय पर डिलीवरी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण लोग गैस एजेंसियों के बाहर इंतजार करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय हालात के कारण लोगों में चिंता का माहौल है और वे जल्द से जल्द गैस सिलेंडर लेना चाहते हैं। लोगों ने यह भी कहा कि मौजूदा तनाव और संघर्ष जल्द खत्म होना चाहिए ताकि आम जनता पर इसका असर न पड़े। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि देश में रसोई गैस और पेट्रोल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और लोगों को घबराने या पैनिक में खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। इस संबंध में इंडियन रसोई गैस की आर एर पूरा ऑफिस के मैनेजर कृष्ण लाल ने बातचीत में बताया कि उनके पास जितना भी गैस का भंडार उपलब्ध है, उसके अनुसार सभी उपभोक्ताओं को रसोई गैस उपलब्ध करवाई जाएगी और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है।

जनगणना-2027 की तैयारियों के लिए मंडी में दूसरे बैच का प्रशिक्षण आरंभ

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

जनगणना-2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की तैयारियों के तहत मंडी के डीआरडीए सभागार में तीन दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे बैच का प्रशिक्षण आरंभ हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ मंडलायुक्त आर.के. पृथ्वी ने किया। इस अवसर पर उपायुक्त एवं जिला जनगणना अधिकारी अर्पू देवान, एडीएम डॉ मदन कुमार तथा जिला राजस्व अधिकारी हरीश शर्मा भी उपस्थित रहे। मंडलायुक्त आर.के. पृथ्वी ने प्रशिक्षण प्राप्त करने जा रहे अधिकारियों और कर्मचारियों से प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने और इसकी बारीकियों को अच्छी तरह समझने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हाउस लिस्टिंग का डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और डेटा



की गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी, भविष्य की योजना निर्माण प्रक्रिया भी उतनी ही प्रभावी होगी। उन्होंने अधिकारियों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है और इसमें किसी प्रकार की शंका या त्रुटि की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मंडलायुक्त ने बताया कि जनगणना-2027 दो चरणों में संचालित की जाएगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी।

बडू भरवाना तक पहुंचाएंगे 32 करोड़ से निमार्णाधीन पेयजल योजना से पानी : यादविंद्र गोमा

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

आयुष, युवा सेवाएं तथा खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा कि पलम क्षेत्र के लिए निमार्णाधीन 32 करोड़ की पेयजल योजना से सरकार पंचरुखी क्षेत्र के लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना का पानी बडू भरवाना क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आयुष, युवा सेवाएं तथा खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने यह बात वीरवार को आयोजित आयुष मेले में बतौर मुख्यअतिथि कही। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए एनसीसी लॉगो को पालमपुर क्षेत्र को योजनाओं पर निर्भर रहना पड़ता था लेकिन अब क्षेत्र को जल्द अपनी पेयजल योजना मिलने जा रही है। इसके अलावा पंचरुखी में अस्पताल भवन भी जुलाई माह तक तैयार करने की बात मंत्री ने कही। इस कार्य के लिए हाल ही में उन्होंने 2 करोड़ रुपए मंजूर करवाए हैं। उन्होंने



कहा कि स्थानीय सड़क के चौड़ीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए नार्बाड से स्वीकृत हुए हैं। जल्द इस पर भी कार्य शुरू होगा। गोमा ने कहा कि प्रदेश सरकार आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी पारंपरिक पद्धतियों ने केवल रोगों के उपचार में सहायक हैं, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में

ईद और नवरात्रि को लेकर तैयारियां तेज, डीसी कठुआ ने विभागों को दिए निर्देश

कठुआ। आगामी ईद और नवरात्रि पर्व को शान्तिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से मनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, निर्बाध बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, सफाई व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक प्रबंधन और परिवहन व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। डिप्टी कमिश्नर ने जल शक्ति विभाग को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने तथा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को त्योहारों के दौरान बिना बाधा बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बाजारों में कालाबाजारी और अधिक कीमत वसूलने पर रोके लगाने के लिए संबंधित विभागों को नियमित मार्केट वेंकिंग करने को कहा गया। ट्रैफिक विभाग को भी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं भी रखीं, जिनके समाधान का भरोसा डीसी ने प्रथमिकता के आधार पर दिलाया। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि त्योहारों के दौरान शांति, भाईचारा और आपसी सद्भाव बनाए रखते हुए प्रशासन का सहयोग करें।

जसरोटिया ने 33 लाख रुपये के विकास कार्यों का किया शुभारंभ

एजेंसी (हि.स.)
कठुआ/जसरोटा

जसरोटा के विधायक राजीव जसरोटिया ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से ब्लॉक कीर्धिया गंडियाल के अंतर्गत पंचायत हटली, रसूह और होट में करीब 33 लाख रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इन कार्यों में मुख्य रूप से गली-नालियों का निर्माण और दोन्ना बिजली ट्रांसफार्मरों की स्थापना शामिल है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गांवों में आंतरिक संपर्क मार्गों को बेहतर बनाना, जलनिक्साी व्यवस्था को मजबूत करना और बिजली आपूर्ति को स्थिर करना है। लंबे समय से स्थानीय लोगों द्वारा इन कार्यों की मांग की जा रही थी जिनके शुरू होने से क्षेत्र के निवासियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। ग्रामीणों ने इन विकास कार्यों की शुरुआत पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे बरसात के दौरान जलभराव, खराब आंतरिक सड़कों और अनियमित



बिजली आपूर्ति जैसी समस्याओं से काफी हद तक निजात मिलेगी। इस मौके पर विधायक राजीव जसरोटिया ने कहा कि जसरोटा विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास उनकी प्राथमिकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत आधारभूत ढांचा तैयार करना संतुलित विकास के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर गांव तक पहुंचाना और बुनियादी सेवाएं बेहतर बनाना उनका मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि सही तरीके से बनी गलियां और नालियां न केवल स्वच्छता बनाए रखने में मदद करती हैं बल्कि बरसात के समय लोगों की आवाजाही को भी आसान बनाती हैं। वहीं नए ट्रांसफार्मर लगने से बिजली व्यवस्था पर पड़ने वाला दबाव कम होगा।

शिमला में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं, लोग अनावश्यक मंडारण न करें: उपायुक्त

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

जिला शिमला में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की आपूर्ति को लेकर प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिले में इन आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है और नियमित रूप से आपूर्ति जारी है। उपायुक्त शिमला अनुमन करण ने लोगों से अपील की है कि वे घबराहट में आकर पेट्रोलिंगम उत्पादों या गैस का अनावश्यक भंडारण न करें, क्योंकि इससे कृत्रिम कमी की स्थिति पैदा हो सकती है। उपायुक्त ने गुरुवार को जिले के सभी उपमंडल दंडाधिकारियों (एसडीएम) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक कर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की आपूर्ति की समीक्षा की। इस बैठक में तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों में उपलब्ध स्टॉक और आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा की गई। अनुमन करण ने बताया कि वर्तमान में जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और नियमित रूप से आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और वे सामान्य रूप से ही इन वस्तुओं का उपयोग करें। उपायुक्त ने यह भी बताया कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए तेल विपणन कंपनियों ने एलपीजी आपूर्ति को लेकर कुछ एहतियाती कदम उठाए हैं। फिलहाल होटल, रेस्टोरेंट और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग होने वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावितता के आश्चर्य के केवल प्राथमिकता और शैक्षणिक संस्थानों को दी जा रही है। अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अस्थायी रूप से आपूर्ति में कुछ प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है।

मौसम 15 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना

हिमाचल प्रदेश में ऊंचे इलाकों में बर्फबारी

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ताजा हिमपात का दौर शुरू हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक-रुक कर बर्फबारी हो रही है। ताजा हिमपात के कारण लाहौल-स्पीति में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मनाली-लेह सड़क को जिससे से आगे वाहनों के लिए बंद कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि बर्फबारी और फिसलन के कारण सड़क पर आवाजाही फिलहाल सुरक्षित नहीं है। राजधानी शिमला और आसपास के इलाकों में गुरुवार सुबह से बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में हल्की गिरावट महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश



और तेज हवाओं की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफतार से अंधड़ चल सकता है और बिजली कड़कने की भी आशंका है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य के कई शहरों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। शिमला में अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 8 डिग्री अधिक है। सुंदरनगर में तापमान 12.6 डिग्री, भुंतर में 13.0 डिग्री और कल्पा में 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। धर्मशाला में 11.5 डिग्री और ऊना में 14.4 डिग्री तापमान दर्ज

हुआ, जबकि नाहन में 17.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। कुल्लू जिले के मनाली में तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस रहा। कांगड़ा में 16.2 डिग्री और पालमपुर में 16.0 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मंडी में 13.3 डिग्री, बिलासपुर में 15.5 डिग्री और सोलान में 11.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। जुब्बड़हट्टी में 15.6 डिग्री, कुफरी में 10.5 डिग्री, कुकुमसेरी में 2.0 डिग्री और तावों में 4.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा कसौली में 17.2 डिग्री, पांवटा साहिब में 17.0 डिग्री, सराहन में 9.0 डिग्री और देहरा गोपीपुर में 16.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक केलंग में 4 मिलीमीटर, कुकुमसेरी में 1.3 मिलीमीटर, जोत में 1 मिलीमीटर और कांगड़ा में 0.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि पालमपुर और धर्मशाला में हल्की बूंदबूंदी दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि 13 मार्च को राज्य में मौसम सामान्य और शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि 13 और 14 मार्च को कुछ क्षेत्रों में लू चलने का थेलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 15 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है तथा इसके असर से मौसम फिर बदल सकता है। विभाग के अनुसार 15 और 16 मार्च को राज्य के अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है और इसके लिए थेलो अलर्ट जारी किया गया है।

संक्षिप्त-समाचार

हिमाचल में 23 मार्च तक ट्रेजरी में जमा करने होंगे बिल, विभागों को निर्देश जारी

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के समापन को लेकर सभी जिलों के उपायुक्तों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वित्त वर्ष के अंतिम दिनों में ट्रेजरी पर भीड़ और तकलीफों दिखने से बचने के लिए सरकार विभागों को अपने बिल तथा समय से पहले जमा करने होंगे। वित्त विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार ट्रेजरी से जुड़े सभी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सभी लेन-देन 31 मार्च 2026 की रात 12 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए अंतिम दिनों में अधिक दबाव से बचने और आरबीआई को भुगतान से जुड़ी फाइलों को समय पर प्रोसेस करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह व्यवस्था की गई है। विभाग ने कहा है कि सरकार विभागों द्वारा धनराशि निकालने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले सभी बिल 23 मार्च को शाम 5 बजे तक संबंधित ट्रेजरी में जमा कराना अनिवार्य होगा। हालांकि जनजातीय क्षेत्रों में यह समय सीमा दो दिन अधिक रखी गई है और वहां के विभाग 25 मार्च को शाम 5 बजे तक अपने बिल ट्रेजरी में प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि ट्रेजरी कार्यालय 31 मार्च को अधिकतम शाम 5 बजे तक संबंधित बैंकों को पे-ऑर्डर जारी कर देंगे, ताकि बैंकों को भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य वित्त वर्ष के अंतिम दिनों में ट्रेजरी और बैंकों पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को कम करना और भुगतान से जुड़े काम को समय पर पूरा करना है।

पुलिस ने फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाने वाले व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच शुरू की

जम्मू। पुलिस ने कमल सिंह जमवाल की पृष्ठभूमि की विस्तृत जांच शुरू कर दी है जिस पर जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की हत्या का प्रयास करने का आरोप है। अधिकारियों ने गुरुवार को जानकारी दी कि पुलिस 63 वर्षीय जमवाल की पृष्ठभूमि की जांच कर रही है जिसमें उसके व्यक्तिगत, सामाजिक और संचािधित संगठनात्मक संबंध शामिल हैं ताकि गोलीबारी की घटना के पीछे के मकसद का पता लगाया जा सके। बुधवार तक जम्मू के बाहरी इलाके ग्रेटर केलाश में शहीद समारोह से निकलते समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अब्दुल्ला बाल-बाल बच गए जब आरोपी ने उन पर पीछे से गोली चलाई। अब्दुल्ला के साथ तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास को विफल कर दिया। जमवाल के पास से एक लाइसेंस पिस्तौल बरामद की गई है जिसका कथित तौर पर अपराध में इस्तेमाल किया गया था। घटना के समय उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी और मुख्यमंत्री प्रमोद अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर अस्तनम वानी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख के साथ थे। जम्मू के पुरानी मंडी निवासी जमवाल ने पुलिस को बताया कि वह पिछले 20 वर्षों से अब्दुल्ला को निशाना बनाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस हमले से पहले उसकी गतिविधियों और आवाजाही की भी जांच कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रत्नमान में जमवाल से पूछताछ कर रहे हैं जिसने जांचकर्ताओं को बताया कि वह अपनी दुकानों से प्राप्त किराए से अपना जीवन यापन करता है। अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी हथियार लेकर कार्यक्रम में कैसे प्रवेश करने में सफल रहा।

शहरी आवास योजना के तहत 58 लाभार्थियों को मिले मकान

मंडी। मंडी जिला धर्मपुर क्षेत्र के विधायक चंद्रशेखर ने शहरी आवास योजना के अंतर्गत नगर पंचायत संघोल और धर्मपुर के 58 पात्र लाभार्थियों को मकान के स्वीकृति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर जरूरतमंद परिवार को सुरक्षित और शहरी आवास उपलब्ध करवाना है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मकान के निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा धर्मपुर के मण्डप, सज्याओ पिपलू, मही और गद्दीधर में सीबीएसई स्कूल प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम लागू करना और सीबीएसई स्कूलों की स्थापना सरकार की दूरदर्शी शिक्षा नीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान से 5वें स्थान तक पहुंचने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। जल्द ही नगर पंचायत क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट, कूड़ा प्रबंधन और सीवेज सिस्टम जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ किया जाएगा, जिससे लोगों को बेहतर शहरी सुविधाएं मिल सकें।

परीक्षा तनाव कम करने के लिए योग व ध्यान पर कार्यशाला आयोजित

जम्मू। छात्रों में परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव को कम करने और उनकी एकाग्रता व मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जम्मू में एक दिवसीय कार्यशाला योग एंड मेडिटेशन फॉर एग्जामिनेशन स्ट्रेस रिडक्शन आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन स्टूडेंट वेल्फेयर कमेटी, साइकोलॉजिकल काउंसिलिंग सेल और रिजर्व एंड डेवलपमेंट सेल के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम प्रिंसिपल प्रो. ज्योति उरुहरे के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए छात्रों को परीक्षा के समय मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए योग और ध्यान जैसी स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए प्रेरित किया।

सिटी दर्पण
जम्मू-कश्मीर

न्योनैपक: रव. कृष्णा शर्मा
स्व. गोता शर्मा

संस्थापक: सतपथ शर्मा

रवामी, प्रकाशक मद्रक एवं संपादक भूमिद शर्मा द्वारा इंग्लैन्ड सिटी एंड पेकेस लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्रांड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकुला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 80/11, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़ में प्रकाशित-160036

सभी विचारों का केंद्र न्यायलक्ष चंडीगढ़ होगा।

स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpn1@gmail.com

सिधरावली हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिजनों को मिली वित्तीय सहायता

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मृतकों के परिजनों को प्रदान किए 20-20 लाख रुपए के चेक

सिटी दर्पण संवाददाता चंडीगढ़

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने आज गुरुग्राम में सिधरावली गांव में सिग्नेचर ग्लोबल की निर्माणधीन साइट पर बीते दिनों हुए हादसे में जान गंवाने वाले सात श्रमिकों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 20-20 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। साथ ही सभी मृतकों के परिजनों को यात्रा खर्च के लिए 20-20 हजार रुपए की वित्तीय सहायता भी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने गुरुवार को गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेट हाऊस में मृतक श्रमिकों के परिजनों से मुलाकात की और दुःख की घड़ी में ढाढस बंधाया।

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने हादसे को लेकर बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नयब सिंह सैनी से बातचीत की थी। मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिजनों की हर प्रकार से सहायता का



आश्वासन दिया। साथ ही आश्वस्त किया कि हरियाणा सरकार दुःख की इस घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री से बातचीत के उपरांत वे झारखंड के जमशेदपुर से सांसद श्री

विद्युत बरन महतो के साथ बुधवार की देर शाम गुरुग्राम पहुंचे और मृतक श्रमिकों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने हादसे के उपरांत त्वरित कार्रवाई करने व पीड़ित परिवारों की

संवेदी भाव से मदद करने के लिए मुख्यमंत्री श्री नयब सिंह सैनी का आभार भी जताया। इस अवसर पर उपयुक्त गुरुग्राम श्री अजय कुमार तथा सीपी श्री विकास अरोड़ा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि बीती 9 मार्च की शाम गुरुग्राम जिला के गांव सिधरावली में सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी की साइट पर मिट्टी खिसकने से सात श्रमिकों नामतः शिवशंकर, परमेश्वर महतो, मंगल महतो, भागीरथ गोपे, संजीव गोपे, धनंजय गोपे निवासी झारखंड तथा सतीश निवासी राजस्थान की मौत हो गई जबकि चार अन्य श्रमिक घायल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने मृतकों के परिजनों को हरियाणा सरकार की सहायता व दुर्घटना को लेकर की जा रही कार्रवाई के बारे में भी जानकारी दी। गुरुग्राम के उपयुक्त अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 20-20 लाख रुपए की सहायता के अतिरिक्त

मृतकों के परिजनों को हरियाणा सरकार के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (बीओसी) कल्याण फंड से 4 लाख रुपए तथा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत 15 लाख रुपए से अधिक की सहायता भी दी जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक परिवार को कुल मिलाकर लगभग 40 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिल सकेगी। उन्होंने हादसे के उपरांत जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। हादसे के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर दिनेश वीर और स्ट्रक्चर इंजीनियर विकास को गिरफ्तार किया। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस दौरान श्रम विभाग के कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट अनिल शर्मा, एगलसी कुशल कटारिया, मानेसर के एसडीएम दर्शन यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

प्रदेश में 100 स्वास्थ्य संस्थान बने फर्स्ट रेफरल यूनिट : आरती राव

सिटी दर्पण संवाददाता चंडीगढ़

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के तहत प्रदेश में द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 100 स्वास्थ्य संस्थानों को फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफआरयू) के रूप में नामित किया है। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि गंभीर मामलों में मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके।

उन्होंने बताया कि इन एफआरयू को 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए विकसित किया जा रहा है। इनके तहत प्रसूति सेवाएं, नवजात शिशु देखभाल तथा रक्त भंडारण जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे माताओं और नवजात शिशुओं से जुड़ी आपात स्थितियों में तुरंत और प्रभावी चिकित्सा सहायता मिल सकेगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये फर्स्ट रेफरल यूनिट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों



और तृतीयक अस्पतालों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करेंगी। सरकार द्वारा इन केंद्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, विशेषज्ञ चिकित्सा स्टाफ को तैनात करने और रेफरल व्यवस्था को तेज व प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि इस पहल के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य हरियाणा में मातृ और नवजात मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाना है। इन एफआरयू के सुदृढ़ होने से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध होगा, जिससे पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार होगा।

प्रदेश में जिन 100 स्वास्थ्य

- एफआरयू के सुदृढ़ होने से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध होगा
- पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार होगा

संस्थानों को फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफआरयू) के रूप में नामित किया है उनमें अंबाला जिला के 5 संस्थान हैं। इनमें अंबाला, भिवानी के 4, चरखी दादरी के 2, फरीदाबाद के 5, फतेहाबाद के भी 5, गुरुग्राम के 4, हिसार के 5, झज्जर के 6, जींद के 6, कैथल के 4, करनाल के 6, कुरुक्षेत्र के 5, महेंद्रगढ़ के 4, नूंह के 5, पलवल के 4, पंचकूला के 4, पानीपत के 4, रेवाड़ी के 4, रोहतक के 4, सिरसा के 5, सोनीपत के 5 तथा यमुनानगर जिला के 4 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को एफआरयू के तौर पर नामित किया गया है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय फोक्स में स्टेम मेला आयोजित



सिटी दर्पण संवाददाता बराड़ा

राजकीय माध्यमिक विद्यालय फोक्स में स्टेम मेले का आयोजन किया गया। यह आयोजन स्कूल इंचार्ज संजीव कुमार के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस मेले में साइंस मास्टर राजेंद्र कुमार के निर्देशन में बाल वैज्ञानिकों ने स्टेम मंच के अंतर्गत विभिन्न चरणों में विभिन्न गतिविधियों का समायोजन किया, जो विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पर आधारित थीं। इन गतिविधियों ने बच्चों को वैज्ञानिक समझ को विकसित करने

हरियाणा के राज्यपाल ने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ मनाया जन्मदिन

सिटी दर्पण संवाददाता पंचकूला

हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर सेक्टर-15 स्थित रेड क्रॉस वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों के साथ अपना जन्मदिन मनाया और उनके साथ खुशी साझा की। इस अवसर पर राज्यपाल की धर्मपत्नी श्रीमती मित्रा घोष भी उपस्थित रहीं। राज्यपाल ने वृद्धाश्रम का दौरा किया और वहां रह रहे बुजुर्गों से बातचीत कर उनका कुशलक्षेम जाना। बुजुर्ग भी अपने बीच राज्यपाल को पाकर बेहद प्रसन्न नजर आए। उन्होंने राज्यपाल से कैक कटवाया और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। राज्यपाल ने भी सभी 22 बुजुर्गों (13 पुरुष और 9 महिलाएं) को शॉल भेंट कर उनका सम्मान किया।



इससे पहले राज्यपाल ने वृद्धाश्रम में विशेष बच्चों के लिए संचालित फिजियोथेरेपी सेंटर का अवलोकन किया और बच्चों के शारीरिक विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया तथा उन्हें रिफ्लेक्टिव किट वितरित की।

राज्यपाल ने बताया कि अब तक रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा के पास चार एम्बुलेंस थीं। आज उन्होंने हरियाणा लोक भवन, चंडीगढ़ से दस नई एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाई है और नौ नई एम्बुलेंस खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपये की राशि भी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के राज्यपाल के रूप में उनका सपना है कि राज्य के प्रत्येक जिले में रेड

बातचीत करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर उन्होंने वृद्धाश्रम के बेहतर रखरखाव और आवश्यक सुविधाओं के लिए 5 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा भी की।

उन्होंने वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी की सहायता भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जाए और आवश्यकता अनुसार उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वे सुखद और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री डी. के. बेहरा, उपयुक्त श्री सतपाल शर्मा, पुलिस उपयुक्त सृष्टि गुप्ता, एएसडीएम श्री चंद्रकांत कटारिया, रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा ब्रांच के उपाध्यक्ष श्री अंकुश मिंगलानी, महासचिव डॉ. सुनील कुमार, संयुक्त सचिव श्री अश्विन जोशी तथा जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की सचिव श्रीमती सविता अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

संक्षिप्त-समाचार

मुख्यमंत्री सैनी ने प्रकट की शोक संवेदनाएं

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयब सिंह सैनी ने वीरवार को कैथल पहुंचकर शोक संवेदनाएं प्रकट कीं। सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री नयब सिंह सैनी हेफेड के पूर्व चेयरमैन कैलाश भगत के पिता स्व. अमरनाथ भगत के निधन पर शोक प्रकट करने उनके आवास पर पहुंचे। जहां उन्होंने परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं। विदिता रहे कि अमरनाथ भगत वरिष्ठ भाजपा नेता थे जिनका गत आठ मर्च को निधन हो गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री नयब सिंह सैनी पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा के आवास पर पहुंचे। जहां उन्होंने पिता स्व. जगत सिंह मलिक के निधन पर शोक जताया। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री नयब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य संजय चौधरी के घर पहुंचे। जहां उनकी माता स्व. शकुंतला देवी के निधन पर शोक जताया और संवेदनाएं प्रकट कीं। इस अवसर पर उनके साथ हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

अनिल कुमार दून पिहोवा मेला-2026 के लिए मेला प्रशासक नियुक्त

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने एचसीएस अधिकारी श्री अनिल कुमार दून, जोकि पिहोवा के उमडंडल अधिकारी (नागरिक) हैं, को पिहोवा मेला-2026 के लिए मेला प्रशासक नियुक्त किया है। यह मेला 17 मार्च से 19 मार्च, 2026 तक आयोजित किया जाएगा।

नाबार्ड द्वारा ग्रामीण भारत महोत्सव - प्रदर्शनी एवं बिक्री का आयोजन 22 मार्च तक

चंडीगढ़। नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) के हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ह्यूमाणीय भारत महोत्सव प्रदर्शनी एवं बिक्री का आयोजन 13 से 22 मार्च 2026 तक चंडीगढ़ के सेक्टर-34 स्थित एज्युबिशन ग्राउंड में किया जाएगा। 10 दिवसीय प्रदर्शनी एवं बिक्री महोत्सव में भारत की समृद्ध ग्रामीण विरासत, पारंपरिक शिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। प्रदर्शनी प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक लगाई जाएगी। इस महोत्सव में देश के 20 राज्यों से आए कारीगरों, बुनकरों, स्वयं सहायता समूह (स्वच्छ) की महिलाओं तथा किसानों द्वारा लगभग 40 स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्टॉलों पर उत्पाद बिक्री के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। इस प्रदर्शनी में नागरिकों को विभिन्न प्रकार के ग्रामीण उत्पाद देखने और खरीदने का अवसर मिलेगा। इनमें मधुबनी एवं गोंड पेंटिंग्स, डोकरा कला, बांस एवं बेंत के उत्पाद, फुलकारी, पशमीना, होम फर्निशिंग और सिल्क वस्त्र जैसे पारंपरिक शिल्प विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसके अतिरिक्त जैविक मसाले, अचार और ड्राई फ्रूट्स जैसे उत्पाद भी उपलब्ध होंगे। विभिन्न प्रदेशों के पकवानों की स्टॉल भी लगाई जाएंगी। नाबार्ड के प्रवक्ता ने बताया कि इस महोत्सव में बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचकर ग्रामीण कारीगरों, बुनकरों और महिला उद्यमियों को न केवल प्रोत्साहित करें बल्कि हस्तनिर्मित उत्पादों को खरीदकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दें।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवेदन आमंत्रित

पंचकूला। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अंत्योदय हरियाणा द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रोजगार के नए अवसर सृजित करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला कल्याण अधिकारी श्री विशाल ने बताया कि आवेदन करने की इच्छुक महिलाओं के पास मान्य (वैलिड) टू-व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिस पर किसी प्रकार का सर्वेक्षण या डिसक्वालिफिकेशन न हो। आवेदिका को 1-2 वर्ष का राइडिंग अनुभव हो। आवेदिका को सोनीपत, करनाल, पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सिरसा या रेवाड़ी जिलों में निवास का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

उपायुक्त ने जनगणना-2027 प्रशिक्षण कार्यशाला का किया शुभारंभ

सिटी दर्पण संवाददाता पंचकूला

उपायुक्त एवं मुख्य जिला जनगणना अधिकारी श्री सतपाल शर्मा ने जनगणना-2027 को डिजिटल मोड में सफलतापूर्वक पूरा करवाने के उद्देश्य से आज सेक्टर-1 स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में तहसीलदारों व शहरी निकायों के अधिकारियों की दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया। उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने अधिकारियों को गंभीरता से जनगणना-2027 का प्रशिक्षण लेने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पहली बार जनगणना में डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जाएगा इसलिए सभी अधिकारी तकनीकी पहलुओं की जानकारी गंभीरता से लें। उन्होंने कहा कि तहसीलदार व नगर निकायों के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में जनगणना कार्य से जुड़े कर्मचारियों को समय रहते प्रशिक्षित करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी डिजिटल



एप्लिकेशन तथा निर्धारित प्रक्रिया से भरती-भाति परिचित हो। उन्होंने बताया कि जनगणना में पहली बार स्वगणना की शुरुआत भी की जाएगी, आजादी के बाद जनगणना-2027 आठवीं जनगणना होगी। उन्होंने बताया कि जनगणना का उल्लेख संविधान में 32 बार किया गया है। सभी अधिकारी गंभीरता से प्रशिक्षण लेकर जनगणना के कार्य को सफलतापूर्वक अपने-अपने क्षेत्रों में पूरा करवाएं। उन्होंने बताया कि जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण मकान सूचिकरण यानि की मकान जनगणना, दूसरा चरण जनसंख्या

एचसीएस अधिकारियों की एपीआर अब ऑनलाइन दर्ज होगी

सिटी दर्पण संवाददाता चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों की वर्ष 2025-26 की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) राज्य के इंटरनेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में जारी एक पत्र के अनुसार एचसीएस अधिकारियों की पीएआर वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज की जाएगी और इसे 31 दिसंबर, 2026 तक अंतिम रूप देना अनिवार्य होगा। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों तथा बोर्डों और निर्माणों के प्रमुखों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पत्र के अनुसार, अधिकारी एचआरएमएस पोर्टल पर



उपलब्ध अपने पेयी कोड और पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। सत्यापन के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त डिजिटल सिग्नेचर सॉफ्टवेयर (डीएससी) अथवा स्कैन किए गए हस्ताक्षर अपलोड कर भी प्रमाणिकरण किया जा सकेगा।

अधिकारियों को 31 मई तक अपना स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत करना होगा। रिपोर्टिंग प्राधिकारी को 31 जुलाई तक मूल्यांकन पूरा करना होगा। रिव्यूिंग प्राधिकारी को 30 सितंबर तक

समीक्षा करनी होगी, जबकि स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा 31 दिसंबर, 2026 तक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। 40 वर्ष से अधिक आयु के एचसीएस अधिकारियों के लिए स्वास्थ्य जांच अनिवार्य की गई है और स्व-मूल्यांकन के साथ मेडिकल रिपोर्ट का सारांश भी अपलोड करना होगा।

पत्र के अनुसार कार्य निष्पादन का मूल्यांकन 1 से 10 के पैमाने पर संख्यात्मक ग्रेडिंग प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इसमें कार्य निष्पादन, व्यक्तिगत गुणों तथा कार्यात्मक दक्षताओं को शामिल किया जाएगा। ऑनलाइन प्रणाली में यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो रिपोर्ट स्वतः अगले स्तर पर अप्रेषित हो जाएगी, ताकि मूल्यांकन प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।

स्वच्छता सरकार की जिम्मेदारी के साथ-साथ समाज के हर नागरिक का भी है नैतिक कर्तव्य: गौरव गौतम

सिटी दर्पण संवाददाता चंडीगढ़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रदेश के खेल राज्यमंत्री श्री गौरव गौतम ने आज पलवल स्थित अनाज मंडी में आयोजित स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कूड़ेदान वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर लगभग 250 कूड़ेदान वितरित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य बाजार क्षेत्र को स्वच्छ, व्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।

खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने अनाज मंडी के दुकानदारों और आड़तियों को कूड़ेदान वितरित करते हुए उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सरकार की जिम्मेदारी के साथ-साथ समाज के हर नागरिक का भी नैतिक कर्तव्य है। यदि सभी लोग मिलकर अपने आसपास सफाई बनाए रखने का संकल्प

- पलवल अनाज मंडी में स्वच्छता अभियान को मिली नई गति, खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने 250 कूड़ेदान किए वितरित

लें, तो शहरों और बाजारों को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी और सब्जी मंडी किसी भी शहर की आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र होती हैं। यहां रोजाना हजारों लोग खरीदारी के लिए आते हैं, इसलिए इन स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे कचरा ड़्धर-उधर फेंकने के बजाय कूड़ेदान में डालें और अपने श्रद्धकों को भी स्वच्छता के प्रति प्रेरित करें। खेल राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार प्रदेश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

सिटी दर्पण संवाददाता पंचकूला

पारदर्शिता, गुणवत्ता और बेहतर क्षेत्रीय निगरानी को मजबूत करने की सुविधा को जारी रखते हुए नगर निगम पंचकूला के आयुक्त श्री विनय कुमार ने आने वाले सप्ताह के लिए निरीक्षण शोड्यूल पहले ही जारी कर दिया है। निरीक्षण शोड्यूल को अग्रिम रूप से जारी करने का उद्देश्य क्षेत्रीय स्टाफ की तैयारी को बेहतर बनाना, नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर निगम सेवाओं की प्रभावो निगरानी सुनिश्चित करना है। निरीक्षण प्रातः 7:30 बजे से शुरू होंगे और शहर के विभिन्न सेक्टरों व वार्डों में किए जाएंगे। आयुक्त तय रूट प्लान के अनुसार सफाई व्यवस्था, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, कचरा संवेदनशील बिंदुओं, सड़कों की सफाई तथा चल

रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

शोड्यूल के अनुसार 18 मार्च को सेक्टर-16, 19 मार्च को सेक्टर-17, 20 मार्च को सेक्टर-18 और 21 मार्च 2026 को सेक्टर-8 में निरीक्षण किए जाएंगे। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने और नागरिक प्रशासन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रूट प्लान पहले ही संबंधित अधिकारियों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (पहअ) और मार्केट एसोसिएशन के साथ साझा कर दिए गए हैं। इन निरीक्षणों का प्रभाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक मूल्यांकन कदम उठाते हुए शोड्यूल में एक दिन पिछले सप्ताह कवर किए गए क्षेत्रों के औचक निरीक्षण के लिए आरक्षित किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पहले के दौरों के



दौरान देखे गए सुधार कायम रहें और क्षेत्रीय टीमों लगातार सफाई और सेवा स्तर बनाए रखें।

यह पहल नागरिक सेवाओं पर निरंतर निगरानी बनाए रखने और निरीक्षण अभियानों के दौरान बनी गति

नगर निगम आयुक्त विनय कुमार ने सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए सेक्टर-वार साप्ताहिक निरीक्षण शोड्यूल किया जारी

सिटी दर्पण संवाददाता चंडीगढ़

को जमीनी स्तर पर लंबे समय तक कायम रखने के लिए आयुक्त की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आज प्रातः आयुक्त ने एमडीसी-4, वार्ड नंबर-2 में निरीक्षण किया, जिसमें हाउस नंबर 87 से पीडीएस-410 तक का क्षेत्र कवर

- सेक्टर-16, 17, 18 और 8 के निरीक्षण का एडवांस रूट प्लान आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन के साथ किया साझा
- निरीक्षण की पूर्व सूचना देने का उद्देश्य पारदर्शिता, जनभागीदारी को बढ़ावा देना और सभी सेक्टरों में बेहतर सफाई व सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित करना है: विनय कुमार

किया गया। दौरे के दौरान सफाई व्यवस्था, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और सार्वजनिक स्थानों के रख-रखाव की समीक्षा की गई। आयुक्त ने सफाई कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों से बातचीत की तथा संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में सफाई के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

निरीक्षण अभियान में एक सकारात्मक सामाजिक पहलू जोड़ते हुए आसमान फाउंडेशन के बच्चों ने सफाई और जिम्मेदारी से कचरा निपटाने का संदेश देते हुए एक डांस प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति के माध्यम से नागरिकों को कूड़ा न फैलाने और शहर को स्वच्छ रखने में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। आयुक्त श्री विनय कुमार ने कहा कि नगर निगम पंचकूला शहर भर में नागरिक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी, सामुदायिक जुड़ाव और बेहतर क्षेत्रीय पर्यवेक्षण पर निरंतर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

संपादकीय

ईरान युद्ध का असर: भारत में शान्तियों पर गैस संकट, मेन्यू घटाने को मजबूर परिवार

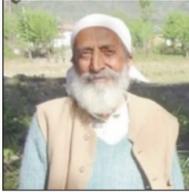
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े युद्ध के प्रभाव अब भारत के घरेलू जीवन और सामाजिक आयोजनों तक पहुंचाए लगे हैं। हजारों किलोमीटर दूर चल रहा यह संघर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। विशेष रूप से रूसी गैस यानी एलपीजी की आपूर्ति में आई बाधाओं ने होटल उद्योग, रेस्तरां और सबसे अधिक शादी समारोहों को प्रभावित किया है। देश के कई हिस्सों में परिवारों के सामने अब एक कठिन विकल्प खड़ा हो गया है—या तो शादी के लिए गैस सिलेंडर का इंटरचेंज करा या फिर भोजन के मेन्यू को छोटा करें। भारत में इन दिनों विवाह का पीक सीजन चल रहा है। लाखों परिवार महीने पहले से तैयारियां करते हैं, बड़ी संख्या में मेहमानों को आमंत्रित किया जाता है और भव्य दावतें आयोजित होती हैं। लेकिन मौजूदा हालात ने इस परंपरा को चुनौती दी है। एलपीजी सिलेंडरों की कमी के कारण कैंटरिंग सेवाओं और विवाह आयोजकों को मेन्यू घटाने, कार्यक्रम छोटा करने या वैकल्पिक ईंधन अपनाने जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। ईरान से जुड़े संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है। खासकर खाड़ी क्षेत्र और हार्मुज जलजमरूमध्य से गुजरने वाले ऊर्जा परिवहन मार्गों में बाधा आने से गैस और तेल की आपूर्ति पर दबाव पड़ा है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और उसका अधिकारियात अयात इसी क्षेत्र से आता है। इसलिए वहां की अस्थिरता का सीधा असर भारतीय बाजार पर दिखाई दे रहा है। ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान के चलते एलपीजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हाल ही में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में लगभग 60 रुपये और व्यावसायिक सिलेंडर में करीब 115 रुपये की वृद्धि हुई है। इससे होटल, रेस्तरां और कैंटरिंग उद्योग की लागत अचानक बढ़ गई है। भारत में शादियों को सामाजिक प्रतिष्ठ और उत्सव का प्रतीक माना जाता है। पारंपरिक तौर पर शादी समारोहों में विस्तृत भोजन व्यवस्था होती है जिसमें कई तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं। लेकिन गैस की कमी के कारण अब कई विवाह आयोजकों को सीमित मेन्यू तैयार करना पड़ रहा है। कई शहरों में कैंटरर्स का कहना है कि

पहले जहां शादी के भोज में 20 से 40 प्रकार के व्यंजन होते थे, अब उन्हें घटाकर 10 से 15 तक करना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर आयोजकों ने मेहमानों की संख्या भी कम कर दी है ताकि सीमित संसाधनों में कार्यक्रम आयोजित किया जा सके। रिपोर्टों के अनुसार देश के कई शहरों—जैसे पुणे, पंजाब, चेन्नई और हैदराबाद—में हजारों शादियां इस संकट से प्रभावित हुई हैं। अनुमान है कि 25 हजार से अधिक विवाह समारोहों पर इसका असर पड़ चुका है। गैस की कमी का सबसे बड़ा असर होटल और कैंटरिंग उद्योग पर पड़ा है, क्योंकि व्यावसायिक रूसी बड़े पैमाने पर 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भर करती है। जब इनकी आपूर्ति बाधित हुई तो कई होटल और विवाह स्थल संचालकों को वाप कार्यक्रम स्थीकरण करने से पहले गैस की उपलब्धता की शर्त रखनी पड़ी। कुछ स्थानों पर होटल और विवाह स्थानों ने कार्यक्रमों की अवधि कम कर दी है, जबकि कई जगह वैकल्पिक ईंधन जैसे लकड़ी, डीजल या इंडव्शन कुकिंग का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि बड़े पैमाने पर भोजन तैयार करने के लिए ये विकल्प पर्याप्त नहीं माने जाते। इसके अलावा गैस सिलेंडरों की कमी के कारण ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतें भी सामने आई हैं। कई व्यापारियों का आरोप है कि सीमित आपूर्ति के कारण सिलेंडर उच्च दामों पर बेचे जा रहे हैं, जिससे लागत और बढ़ रही है। इस संकट ने शादी करने वाले परिवारों को असहजस में डाल दिया है। कई परिवारों ने कैंटरिंग मेन्यू को छोटा करने का फैसला लिया है, जबकि कुछ ने समारोह को साधारण बनाने का विकल्प चुना है। कई आयोजकों का कहना है कि अब परिवार दो विकल्पों पर विचार कर रहे हैं—या तो अतिरिक्त सिलेंडर का इंटरचेंज कर खर्च बढ़ाएं या फिर भोजन में कटौती कर कार्यक्रम को सीमित रखें। इस स्थिति ने उन परिवारों की विशेष रूप से प्रभावित किया है जो पहले से ही शादी के बढ़ते खर्च से जुझ रहे थे। केंद्र सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए कुछ तात्कालिक कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। साथ ही सिलेंडर बुकिंग के बीच की अवधि बढ़ाकर 25 दिन

कर दी गई है ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके। इसके अलावा तेल कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि बाजार में गैस की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। सरकार का कहना है कि पर्यटन उद्योगों और आवश्यक सेवाओं को गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। एलपीजी संकट केवल शादी समारोहों तक सीमित नहीं है। रेस्तरां, होटल, कैटरिंग, मॉडिों और हॉस्टलों की रसोइयों में भी इसका असर देखा जा रहा है। कई स्थानों पर मेन्यू में बदलाव करना पड़ा है और कुछ रेस्तरां को अस्थायी रूप से बंद भी करना पड़ा है। ऊर्जा संकट का यह प्रभाव दशर्तात है कि वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित कर सकती हैं। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से ऊर्जा कीमतें, परिवहन लागत और खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। भारत में शान्तियों केवल पारिवारिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। बड़े भोजन, मेहमानों की मेजबानी और उत्सव का माहौल भारतीय विवाहों की पहचान रहा है। लेकिन गैस संकट के कारण कई परिवार अब सादगीपूर्ण समारोह की ओर बढ़ने को मजबूर हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति भारतीय समाज में शादी समारोहों की भव्यता पर भी पुनर्विचार करने का अवसर बन सकती है। यदि संकट लंबा खिंचता है तो विवाह आयोजन उद्योग को स्थायी रूप से अधिक फिकायाती और ऊर्जा-कुशल विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं। ईरान से जुड़े युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक राजनीति का असर केवल अंतरराष्ट्रीय मंच तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम लोगों की जिंदगी तक पहुंच जाता है। भारत में एलपीजी संकट के कारण शादी जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक आयोजन भी प्रभावित हो रहे हैं। जब तक ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति सामान्य नहीं होती, तब तक परिवारों, होटल उद्योग और कैंटरिंग सेवाओं को सीमित संसाधनों में ही काम चलाना होगा। यह संकट एक बार फिर याद दिलाता है कि वैश्विक ऊर्जा निर्भरता और भू-राजनीतिक तनाव किस तरह हमारे रोजगार के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं।

हिमालयी राज्यों में कशमल का संरक्षण बड़ी चुनौती

कशमल हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली एक बहु उपयोगी औषधि है। इसे चंबा में कसैहल, संस्कृत में दारु हरिद्रा, गढ़वाल में किमोड़ा, हिंदी में दारु हल्दी कहा जाता है। यह झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसकी ऊंचाई 7-8 फुट तक होती है। इसकी तीन-चार प्रजातियां हैं, जो निचले से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगती हैं। कशमल के फल बच्चे चाव से खाते हैं। जंगली जानवरों बंदर आदि का भी पसंदीदा आहार है। इनकी पत्तियां भेड़- बकरी के लिए पौष्टिक चारा है। इसके फूलों पर मधुमक्खी काम करती है। इसकी जड़ों से रसोत नामक औषधि बनाई जाती है। इसके अलावा अनेक बीमारियों तो उपचार में इसका उपयोग होता है। इस वजह से औषधि उद्योग में इसकी बहुत मांग रहती है। इसी कारण कशमल का अवैध दोहन बढ़े पैमाने पर होता रहता है।



कशमल को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। भले ही इसके व्यापारिक दोहन पर सरकारी जंगल से प्रतिबन्ध लगा है किन्तु शांतिर ठेकेदार स्थानीय लोगों को बेवकूफ बना कर साठ-गांठ कर लेते हैं और निजी भूमि से उखाड़ने का परमिट ले लेते हैं, जबकि निजी जमीन में बहुत ही कम मात्र में कशमल उपलब्ध होता है। अतः निजी भूमि के नाम पर असल में दोहन सरकारी जंगलों से होता है।

कुलभूषण उपमन्यु (हि.स) चिपको आन्दोलन के दौर में भटियात क्षेत्र और चंबा के साथ लगते जडेरा क्षेत्र से कशमल संरक्षण के लिए आवाज उठाई गई थी। भटियात के छुआला गांव और धरवाई गांव से करीब एक टुक कशमल की जड़ जो अवैध रूप से निकाली गई थी, आन्दोलनकारियों ने जब्त करवाई थी। जडेरा में बहुत बड़े पैमाने पर अवैध रूप से कशमल उखाड़ा गया था, जिसे जमान बैरियर लगा कर रोक गया था और जब्त करवाया गया था। सरकारी जंगल से कशमल उखाड़ने पर रोक लगी थी। आज तक वह रोक तो जारी है किन्तु अवैध धंधे वाले निजी भूमि से परमिट लेकर सरकारी जंगलों से अवैध रूप से उखाड़ कर ले जाते हैं। गत वर्ष चंबा के चुराह और सलूनी तहसील के कुछ जागरूक लोगों द्वारा इसके विरुद्ध आवाज उठाई गई थी। कांगड़ा के बैजनाथ से भी ऐसी खबरें आई थीं। प्रदेश के दूसरे हिस्सों से भी इस तरह की अवैध रूप से कशमल उखाड़ने की खबरें आती रही हैं।

कुलभूषण उपमन्यु (हि.स)

हैरानी की बात यह है कि जब भी निजी भूमि से कशमल उखाड़ने का परमिट दिया जाता है तो उस भूमि में कितने झाड़ कशमल के हैं यह क्यों नहीं जांचा जाता। अगर परमिट जारी करने के समय यह जांच हो जाए तो पता लग जाएगा कि कितनी मात्रा में कशमल उपलब्ध हो सकती है। निर्धारित मात्रा से ज्यादा जड़ें मिलने पर ठेकेदारों पर शिकंजा कसा जा सकता है। यह जरूरी सावधानी बरती ही जानी चाहिए। इसके अलावा बहुत से देशों में कशमल की खेती की संभावनाओं को भी विकसित किया जा रहा है। हमारे देश में भी कशमल की खेती आरंभ की जानी चाहिए ताकि जंगल से कशमल को न उखाड़ा जाए और अपने खेतों से इसकी फसल तैयार करने की ओर बढ़ा जा सके। इसमें दस से बीस साल का समय तो लगेगा किन्तु खैर आदि तैयार करने में भी तो इतना ही समय लग जाता है। स्थानीय समुदायों में कशमल के जंगलों के आसपास भेड़-बकरी पालन और मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देकर भी स्थानीय लोगों को वैकल्पिक आय उपलब्ध करवाई जा सकती है।

चिपको आन्दोलन के दौर में भटियात क्षेत्र और चंबा के साथ लगते जडेरा क्षेत्र से कशमल संरक्षण के लिए आवाज उठाई गई थी। भटियात के छुआला गांव और धरवाई गांव से करीब एक टुक कशमल की जड़ जो अवैध रूप से निकाली गई थी, आन्दोलनकारियों ने जब्त करवाई थी। जडेरा में बहुत बड़े पैमाने पर अवैध रूप से कशमल उखाड़ा गया था, जिसे जमान बैरियर लगा कर रोक गया था और जब्त करवाया गया था। सरकारी जंगल से कशमल उखाड़ने पर रोक लगी थी। आज तक वह रोक तो जारी है किन्तु अवैध धंधे वाले निजी भूमि से परमिट लेकर सरकारी जंगलों से अवैध रूप से उखाड़ कर ले जाते हैं। गत वर्ष चंबा के चुराह और सलूनी तहसील के कुछ जागरूक लोगों द्वारा इसके विरुद्ध आवाज उठाई गई थी। कांगड़ा के बैजनाथ से भी ऐसी खबरें आई थीं। प्रदेश के दूसरे हिस्सों से भी इस तरह की अवैध रूप से कशमल उखाड़ने की खबरें आती रही हैं।

कुलभूषण उपमन्यु (हि.स)

इससे लोगों का स्वार्थ संरक्षण की दिशा में मोड़ा जा सकता है। इसके लिए वन विभाग को भी अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। अंग्रेजी शासन काल से इन बहुमूल्य जड़ी-बूटियों को वर्किंग प्लान का हिस्सा नहीं बनाया गया जिस कारण इनको उगाने की व्यवस्था भी पनप नहीं सकी। इन्हें लागू वन उपज माना गया। छोटा-मोटा उखाड़ने का परमिट जारी करने और एक्सपोर्ट परमिट जारी करने के बाद अपने कर्तव्यों की इति श्री मान ली गईं। अभी कुछ हद तक चिंता की जाने लगी है किन्तु चाक चौबंद व्यवस्था कब खड़ी होगी कोई नहीं जानता। हर बरसात में बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आ रहे हिमाचल प्रदेश में सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह कशमल और अन्य भूस्खलन रोकने वाली जड़ी-बूटियों और झाड़ियों के संरक्षण के लिए सख्त कदम उठाए, कार्य करे।

स्थानीय स्तर पर 20-30 रुपये, प्रति किलो खरीद कर आगे कंपनियों को भारी मुनाफे पर व्यापारी लोग बेचते हैं। दवाई बन जाने के बाद तो इसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। थोड़े से लाभ के लिए किसान अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। कशमल को बचा कर यदि उस पर भेड़-बकरी पालन और मधुमक्खी पालन किया जाए तो इससे कहीं ज्यादा कमाई किसान कर सकते हैं। इसके अलावा कशमल की जड़ें बहुत गहरी होती हैं जिनको उखाड़ने के लिए 4 ढलानें पड़ते हैं जिनमें एक पहाड़ी ढलानें काटनी होती हैं और बरसात में भूस्खलन का कारण बनती हैं। इसलिए जरूरी है कि

कुलभूषण उपमन्यु (हि.स)

(लेखक, हिमालय नीति अभियान के अध्यक्ष और पर्यावरणविद् हैं।)

निवारक स्वास्थ्य देखभाल में अग्रणी भूमिका निभा रहा है योग

बीते दशकों के युग को केवल पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति के रूप में ही नहीं सराहा गया, बल्कि उसे उत्तरोत्तर रूप से स्वास्थ्य और कल्याण के लिए साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण के रूप में भी पहचाना जाने लगा है। वैज्ञानिक अनुसंधान, डिजिटल नवाचार और वैश्विक सहयोग अब हमें योग को केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत ही नहीं, बल्कि एक सशक्त जन-स्वास्थ्य हस्तक्षेप समझने में भी मदद कर रहे हैं।

मोरांजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) को पारंपरिक चिकित्सा (योग) के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया है और योग अनुसंधान में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका और भी मजबूती प्रदान करते हुए वर्ष 2025-2029 के लिए इसे फिर से निमित्त किया गया है। यह पहचान गैर-संचारी रोग (एनसीडी) के लिए साक्ष्य-आधारित योग हस्तक्षेपों को बढ़ावा देने में संस्थान की बढ़ती भूमिका को दिखाती है। इस पहल के प्रमुख साझेदारों में आयुष मंत्रालय, एम्स दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनल मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, दिल्ली शामिल हैं।



प्रतापराव जाधव

इस सहयोग के माध्यम से केंद्र मधुमेह, मोटापा और तनाव से संबंधित विकारों जैसे गैर-संचारी हस्तक्षेपों पर तकनीकी दिशानिर्देश विकसित कर रहा है और अनुसंधान को आगे बढ़ा रहा है। इन प्रयासों में अंतरराष्ट्रीय संघटन भी साझेदारी कर रहे हैं, जिससे योग की वैज्ञानिक आधारशिला और मजबूत हो रही है तथा निवारक स्वास्थ्य देखभाल के लिए व्यापक रूप से लागू किए जा सकने वाले, फिकायती और साक्ष्य-समर्थित प्रभावी साधन के तौर पर योग की क्षमता प्रदर्शित हो रही है।

मोरांजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) को पारंपरिक चिकित्सा (योग) के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया है और योग अनुसंधान में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका और भी मजबूती प्रदान करते हुए वर्ष 2025-2029 के लिए इसे फिर से निमित्त किया गया है। यह पहचान गैर-संचारी रोग (एनसीडी) के लिए साक्ष्य-आधारित योग हस्तक्षेपों को बढ़ावा देने में संस्थान की बढ़ती भूमिका को दिखाती है। इस पहल के प्रमुख साझेदारों में आयुष मंत्रालय, एम्स दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनल मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, दिल्ली शामिल हैं।

संस्थागत स्तर पर एमडीएनआईवाई योग की वैज्ञानिक आधारशिला को मजबूती प्रदान करना रखे हुए कार्यस्थल योग कार्यक्रम Y-Break – जो काम के दौरान 5-10 मिनट का सरल योग ब्रेक है – से अब तक 33 लाख से अधिक सरकारी अधिकारियों को लाभ मिल चुका है।

प्रतापराव जाधव

इन पहलों से प्राप्त अनुसंधान निष्कर्ष और सहभागिता विश्लेषण अत्यंत उत्साहजनक हैं। Y-Break अभ्यास से कुछ ही सप्ताहों में अग्रभूत तनाव में लगभग 40 प्रतिशत तक कमी देखी गई है। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि इससे मानसिक सतर्कता, भावनात्मक दृढ़ता और निर्णय-क्षमता में सुधार होता है। इसके साथ-साथ कार्टिसोल स्तर जैसे शारीरिक संकेतकों में भी सकारात्मक परिवर्तन पाए गए हैं। शारीरिक लाभों में गर्दन, कंधे और कमर के दर्द में कमी, रवास

मोरांजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) को पारंपरिक चिकित्सा (योग) के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया है और योग अनुसंधान में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका और भी मजबूती प्रदान करते हुए वर्ष 2025-2029 के लिए इसे फिर से निमित्त किया गया है। यह पहचान गैर-संचारी रोग (एनसीडी) के लिए साक्ष्य-आधारित योग हस्तक्षेपों को बढ़ावा देने में संस्थान की बढ़ती भूमिका को दिखाती है। इस पहल के प्रमुख साझेदारों में आयुष मंत्रालय, एम्स दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनल मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, दिल्ली शामिल हैं।

संस्थागत स्तर पर एमडीएनआईवाई योग की वैज्ञानिक आधारशिला को मजबूती प्रदान करना रखे हुए कार्यस्थल योग कार्यक्रम Y-Break – जो काम के दौरान 5-10 मिनट का सरल योग ब्रेक है – से अब तक 33 लाख से अधिक सरकारी अधिकारियों को लाभ मिल चुका है।

प्रतापराव जाधव

इस सहयोग के माध्यम से केंद्र मधुमेह, मोटापा और तनाव से संबंधित विकारों जैसे गैर-संचारी हस्तक्षेपों पर तकनीकी दिशानिर्देश विकसित कर रहा है और अनुसंधान को आगे बढ़ा रहा है। इन प्रयासों में अंतरराष्ट्रीय संघटन भी साझेदारी कर रहे हैं, जिससे योग की वैज्ञानिक आधारशिला और मजबूत हो रही है तथा निवारक स्वास्थ्य देखभाल के लिए व्यापक रूप से लागू किए जा सकने वाले, फिकायती और साक्ष्य-समर्थित प्रभावी साधन के तौर पर योग की क्षमता प्रदर्शित हो रही है।

आज का राशिफल

मेघ: आज आपको आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, खासकर यदि आप किसी से ऋण लेने की योजना बना रहे हैं। विधाथियों के लिए दिन उत्साहजनक और उपलब्धियों से भरा रह सकता है। *(सिटी दर्पण)*

वृषभ: कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी या परिचित व्यक्ति के साथ बहस की स्थिति बन सकती है, जिससे मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। ऐसे में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले थरोसेमंट मित्रों या सलाहकारों से राय लेना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। *(सिटी दर्पण)*

मिथुन: आज कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल देखने को मिलेगा और आपके प्रयासों की सराहना भी हो सकती है। नया वाहन खरीदने या किसी बड़ी वस्तु में निवेश करने का विचार मन में आ सकता है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के अनुभव से आपको महत्वपूर्ण सीख मिलेगी। *(सिटी दर्पण)*

कर्क: आप आज अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने की कोशिश करेंगे। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, जिससे कई उलझे हुए काम सुलझ सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। *(सिटी दर्पण)*

सिंह: सरकारी सेवा या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। परिवार में विशेषकर संतान के व्यवहार से मन दुखी हो सकता है। कुछ बनते हुए कार्यों में बाधा आने की संभावना है, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें। *(सिटी दर्पण)*

कन्या: कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा का दबाव महसूस हो सकता है, जिससे आपको अपनी क्षमता साबित करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। परिवार के किसी सदस्य की जरूरतों पर धन खर्च करना पड़ सकता है। *(सिटी दर्पण)*

तुला: आज आपकी सोच और विचारों का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। व्यापार या व्यवसाय से होने वाली आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और उन्हें कोई उपहार भी दे सकते हैं। आप अपने लक्ष्य को समय से पहले हासिल करने में सफल हो सकते हैं। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिक: आज घर के वातावरण में मन कम लग सकता है और कुछ लोग अपनी गलतियों का दोष आप पर डालने की कोशिश कर सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिभा और गुणों की चर्चा हो सकती है। समुदाय पक्ष के साथ किसी मुद्दे पर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। *(सिटी दर्पण)*

धनु: व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए नए तरीकों और रणनीतियों को अपनाना फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि कई काम आपको अपने दम पर ही पूरे करने पड़ सकते हैं। व्यापार में सुधार होने से पुराने कर्ज से राहत मिलने की संभावना है। *(सिटी दर्पण)*

मकर: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज नए अवसर सामने आ सकते हैं। नौद की कमी के कारण सरिर्द या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम पर ध्यान दें। व्यापारियों को किसी नई डील या निवेश से पहले पूरी जांच-पड़ताल करनी चाहिए। *(सिटी दर्पण)*

कुंभ: संतान की उपलब्धियां आपको गर्व और खुशी का अनुभव करा सकती हैं। मित्र आपके मुश्किल समय में साथ देंगे और समस्याओं को हल करने में मदद करेंगे। साहित्य, लेखन या कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सम्मान और आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। *(सिटी दर्पण)*

मीन: आज आप किसी नए प्रोजेक्ट या निवेश की शुरूआत करने का निर्णय ले सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े अनुबंध समय पर पूरे करने में सफल रहेंगे। दौपत्य जीवन में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा। अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

अंतरराष्ट्रीय संदर्भ, वैश्विक व्यापार चुनौतियां और भारत की रणनीति

अमेरिका में 20 जनवरी, 2025 को डोनाल्ड ट्रम्प के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद वैश्विक आर्थिक और व्यापारिक व्यवस्था में बदलाव आने का संकेत देखा जा रहा है। ट्रम्प ने 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' के नारे के साथ अमेरिकी उद्योग और विनिर्माण को पुनर्जीवित करने की नीति अपनाई। इसी उद्देश्य से उन्होंने विभिन्न देशों से अमेरिका को होने वाले आयात पर भारी टैरिफ लगाने की रणनीति अपनाई। उनका मानना था कि यदि विदेशी उत्पादों पर अधिक शुल्क लगाया जाएगा तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों अमेरिका में ही उत्पादन शुरू करेंगी और इससे अमेरिकी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। यह नीति अत्यंत आक्रामक रूप से लागू

निकालना शुरू कर दिया। इससे शोयर् बाजार में गिरावट आई और विदेशी मुद्रा प्रवाह पर भी दबाव बढ़ा। चूंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है और भारत के निर्यात में उसकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, इसलिए यह कदम भारत के विदेशी व्यापार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया।



प्रह्लाद सबनानी (हि.स)

चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों सहित कई नए बाजारों में इन उत्पादों का निर्यात बढ़ाने का प्रयास किया। वर्ष 2025 में भारत ने वैश्विक व्यापार परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने की दिशा में सक्रिय प्रयास किए। वर्ष के अंत तक भारत ने यूनाइटेड किंगडम, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ महत्वपूर्ण समझौते किए। इसके साथ ही अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ भी व्यापारिक सहयोग को मजबूत करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इन प्रयासों का सकारात्मक परिणाम यह रहा कि नवंबर और दिसंबर 2025 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि बढ़ बनाए रखने में सफलता मिली, जबकि सितंबर और अक्टूबर के महीनों में अमेरिकी बाजार में टैरिफ के कारण कुछ गिरावट देखी गई थी।

ट्रम्प प्रशासन की नीतियां केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहें, बल्कि उनमें साम्राज्यवादी सोच के संकेत भी दिखाई दिए। उदाहरण के तौर पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर अमेरिका में मुकदमा चलाने की घटना ने वैश्विक राजनीति में नई बहस छेड़ दी। अमेरिका की नजर वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर मानी जा रही है। इसके अलावा डेनमार्क के अधीन ग्रीनलैंड द्वीप पर भी अमेरिका ने अपना प्रभाव स्थापित करने की इच्छा जताई। इसी प्रकार मेक्सिको, क्यूबा और ईरान जैसे देशों को भी विभिन्न प्रकार की चेतावनियां दी गईं। इन घटनाओं ने वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक संबंधों में तनाव की स्थिति पैदा कर दी।

भारत और अमेरिका के संबंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन भारत ने इस चुनौती का सामना करने के लिए त्वरित और व्यावहारिक रणनीति अपनाई। सरकार ने वैकल्पिक बाजारों की तलाश शुरू की और कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने की दिशा में तेजी से कदम उठाए। भारत ने विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जो अमेरिका की निर्यात पर अधिक निर्भर थे, जैसे वस्त्र एवं परिधान, जेम्स एवं ज्वेलरी, समुद्री उत्पाद, खिलाता उद्योग और चमड़ा उद्योग। ये सभी श्रम आधारित उद्योग हैं और इनमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। यदि इन क्षेत्रों के निर्यात पर बड़ा संकट आने लगे तो देश में बेरोजगारी की समस्या गंभीर रूप ले सकती थी। इसलिए भारत ने रूस, भारत और अमेरिका के संबंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन भारत ने इस चुनौती का सामना करने के लिए त्वरित और व्यावहारिक रणनीति अपनाई। सरकार ने वैकल्पिक बाजारों की तलाश शुरू की और कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने की दिशा में तेजी से कदम उठाए। भारत ने विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जो अमेरिका की निर्यात पर अधिक निर्भर थे, जैसे वस्त्र एवं परिधान, जेम्स एवं ज्वेलरी, समुद्री उत्पाद, खिलाता उद्योग और चमड़ा उद्योग। ये सभी श्रम आधारित उद्योग हैं और इनमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। यदि इन क्षेत्रों के निर्यात पर बड़ा संकट आने लगे तो देश में बेरोजगारी की समस्या गंभीर रूप ले सकती थी। इसलिए भारत ने रूस,

प्रह्लाद सबनानी (हि.स)

चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों सहित कई नए बाजारों में इन उत्पादों का निर्यात बढ़ाने का प्रयास किया। वर्ष 2025 में भारत ने वैश्विक व्यापार परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने की दिशा में सक्रिय प्रयास किए। वर्ष के अंत तक भारत ने यूनाइटेड किंगडम, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ महत्वपूर्ण समझौते किए। इसके साथ ही अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ भी व्यापारिक सहयोग को मजबूत करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इन प्रयासों का सकारात्मक परिणाम यह रहा कि नवंबर और दिसंबर 2025 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि बढ़ बनाए रखने में सफलता मिली, जबकि सितंबर और अक्टूबर के महीनों में अमेरिकी बाजार में टैरिफ के कारण कुछ गिरावट देखी गई थी।

अमेरिकी प्रशासन का तर्क था कि भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना अप्रत्यक्ष रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध को आर्थिक समर्थन देना है, परिणामस्वरूप 27 अगस्त 2025 से भारत के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लागू कर दिया गया। इस निर्णय का भारत की अर्थव्यवस्था पर तत्काल प्रभाव पड़ा। भारतीय पूंजी बाजार में अस्थिरता बढ़ गई और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजारों से अपना निवेश

भारत और अमेरिका के संबंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन भारत ने इस चुनौती का सामना करने के लिए त्वरित और व्यावहारिक रणनीति अपनाई। सरकार ने वैकल्पिक बाजारों की तलाश शुरू की और कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने की दिशा में तेजी से कदम उठाए। भारत ने विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जो अमेरिका की निर्यात पर अधिक निर्भर थे, जैसे वस्त्र एवं परिधान, जेम्स एवं ज्वेलरी, समुद्री उत्पाद, खिलाता उद्योग और चमड़ा उद्योग। ये सभी श्रम आधारित उद्योग हैं और इनमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। यदि इन क्षेत्रों के निर्यात पर बड़ा संकट आने लगे तो देश में बेरोजगारी की समस्या गंभीर रूप ले सकती थी। इसलिए भारत ने रूस,

प्रह्लाद सबनानी (हि.स)

भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ किए जा रहे मुक्त व्यापार समझौतों से विद्युत समुदाय में सकारात्मक संदेश गया है। भारत 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना के साथ वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रहा है। इन समझौतों से संबंधित देशों की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि व्यापार में वृद्धि से आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इसके परिणामस्वरूप कई देशों का भारत के प्रति दृष्टिकोण भी सकारात्मक हुआ है और वे भारत को एक विश्वसनीय और उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में देखने लगे हैं। हालांकि इन सकारात्मक पहलुओं के बावजूद भारत के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होना है। हाल के समय में एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये से अधिक हो गई है और वर्ष 2025 में रुपये का लगभग 5 से 6 प्रतिशत अममूल्य हुआ है। इसका मुख्य कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय पूंजी बाजार से निवेश निकालना है, जिससे डॉलर की कीमत बढ़ बढ़ गया है। इस समस्या से निपटने के लिए भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने और निर्यात को प्रोत्साहित करने की नीति अपना रहा है। यदि भारत निर्यात में विदेशी निवेश दोनों क्षेत्रों में वृद्धि करने में सफल होता है तो विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा और रुपये पर दबाव कम किया जा सकेगा। समग्र रूप से देखा जाए तो ट्रम्प प्रशासन का आक्रामक व्यापारिक नीतियों ने वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अस्थिरता पैदा की है, लेकिन भारत ने इन चुनौतियों का सामना व्यवहारिक और संतुलित रणनीति से करने का प्रयास किया है। आत्मनिर्भरता, मुक्त व्यापार समझौतों का विस्तार, नए बाजारों की खोज और युवा शक्ति का विकास भारत की प्रमुख रणनीतियां हैं। यदि भारत इन क्षेत्रों में निरंतर प्रगति करता है तो वह न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर स्थिरता और सहयोग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बन सकता है।

(लेखक, आर्थिक मामलों के विश्लेषक एवं स्तम्भकार हैं।)

प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026 व्यापक संभावनाओं के साथ आज से मोहाली में आयोजित किया जाएगा: संजीव अरोड़ा

अरविंद केजरीवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे: संजीव अरोड़ा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली तथा स्थानीय निकायों से संबंधित कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज घोषणा की कि प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026 13 से 15 मार्च तक प्लाक्षा यूनिवर्सिटी, एएसएन नगर (मोहाली) में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन पंजाब को निवेश और नवाचार के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन भारत और विश्व भर के निवेशकों, उद्योगपतियों और नीति निर्माताओं को पंजाब में उपलब्ध व्यापक निवेश अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए श्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि इस सम्मेलन में कुल 89 सत्र आयोजित किए जाएंगे और यह राज्य में अब तक आयोजित सबसे व्यापक निवेश



उज्जगर किया जाएगा। श्री अरोड़ा ने बताया कि अरविंद केजरीवाल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कल सुबह



10:30 बजे सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। इसके बाद दोपहर का भोजन तथा विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे।

सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद है।

उन्होंने आगे कहा कि यह कार्यक्रम नई औद्योगिक और व्यापार विकास नीति के लॉन्च के बाद पंजाब की अपार संभावनाओं को उजागर करेगा, जिसका देश भर के उद्योगपतियों द्वारा व्यापक स्वागत किया गया है। उन्होंने कहा कि उद्यमी पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत निवेशक-अनुकूल नीतिगत ढांचे की सराहना कर रहे हैं।

श्री अरोड़ा ने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार चाहती है कि उद्योग जगत के बड़े प्रतिनिधि आपस में तालमेल स्थापित करें और भविष्य में निवेश के लिए पंजाब द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे व्यापक अवसरों से अवगत हों।

उन्होंने कहा कि मोहाली तेजी से

कांग्रेस विधायक द्वारा स्पीकर, मंत्रियों और आप विधायकों को बंधुआ मजदूर कहना संविधान और जनादेश का अपमान: हरपाल सिंह चीमा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब विधानसभा ने आज बड़े बहुमत से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन (ब्रॉच ऑफ प्रिविलेज) का मामला प्रिविलेज कमेटी को सौंपने के लिए प्रस्ताव पारित किया। कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव में विधायक के हालिया अपमानजनक बयानों और भ्रू-संसदीय व्यवहार का उल्लेख किया गया है, जिसे सदन ने अपने निर्वाचित सदस्यों, संविधान और जनता का सीधा अपमान माना।

प्रस्ताव की पृष्ठभूमि के बारे में बताते हुए कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग विधायक सुखपाल सिंह खैहरा द्वारा 10 मार्च 2026 को की गई सोशल

मीडिया पोस्टों से उठी है। इन सार्वजनिक बयानों में उन्होंने स्पीकर, कैबिनेट मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के विधायकों को बंधुआ मजदूर कहा था।

सदन में प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने कहा, ऐसी शब्दावली संवैधानिक रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस पहुंचाती है और लोगों द्वारा दिए गए जनादेश का अपमान करती है। यह मामला 11 मार्च 2026 को और गंभीर हो गया जब विधायक सुखपाल सिंह खैहरा को सदन में अपने बयानों पर स्पष्टीकरण देने और माफी मांगने का अवसर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने शब्द वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया कि 11 मार्च

मोदी की विदेश नीति ने भारत को बर्बाद किया: हरचंद सिंह बरसट

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

आम आदमी पार्टी, पंजाब के राज्य महासचिव और पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन स. हरचंद सिंह बरसट ने केंद्र की मोदी सरकार की विदेश नीति पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एकतरफा विदेश नीति के कारण आज देश को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में एलपीजी को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है, वह केंद्र सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है।

स. बरसट ने कहा कि भारत पिछले 75 सालों से गुट निरलेप विदेश नीति अपनाता रहा। भारत कभी भी किसी एक पक्ष के साथ नहीं खड़ा हुआ, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में मध्यस्थ भूमिका निभाकर फैसले करवाता रहा है, लेकिन वर्तमान समय में ईरान-इजराइल युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खुले तौर पर इजराइल व अमेरिका का साथ देने के कारण

सिटी दर्पण संवाददाता
मोहाली

सीनियर कांग्रेसी नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्ध ने मोहाली के सेक्टर-70 के निवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनीं और उन्हें जल्द समाधान कराने का भरोसा दिया। सिद्ध ने लोगों को आश्वासित किया कि उनकी जायज मांगों को तुरंत संबंधित विभागों तक पहुंचाकर जल्द से जल्द हल करवाया जाएगा।

इस दौरान सिद्ध ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध रही है और भविष्य में भी जनता की आवाज बनकर काम करती रहेगी। सिद्ध ने कहा कि इलाके के लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी को मोक़ा दिया था, लेकिन अफसोस की



सरकार मोहाली के विकास के लिए कोई बड़ा काम करने में असफल रही है। लोगों को उम्मीद थी कि नई सरकार इलाके के विकास को नई दिशा देगी, लेकिन अफसोस की बात है कि जमीन पर कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय मोहाली में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए थे, जिनमें मेडिकल कॉलेज लाना एक बड़ी उपलब्धि थी। कांग्रेस ने हमेशा मोहाली के समग्र विकास के लिए काम किया है और आगे भी लोगों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी का मूल उद्देश्य लोगों की सेवा करना और समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम करना है। इस मोक़े पर मोहाली के मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्ध, सीनियर डिप्टी मेयर अमरीक सिंह सोमल भी मौजूद थे।

जैतो के पास एस.एस.पी. फरीदकोट डॉ. प्रज्ञा जैन की अगुवाई में 5.37 किलो हैरोइन समेत भारी मात्रा में ड्रग्स पदार्थ नष्ट किए गए

जैतो। श्री गौरव यादव आई.पी.एस. डी.आई.जी. पंजाब के दिशा-निर्देशों पर ड्रग्स के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत फरीदकोट की एस.एस.पी. डॉ. प्रज्ञा जैन की देखरेख में गुरुवार को सेल लिमिटेड पावर प्लांट सेना सिंह बाला में डिस्ट्रिक्ट लेवल ड्रग डिस्कोज कमेटी के सदस्यों ने 5.37 किलो से ज्यादा हैरोइन, 01 किंटवॉल 78 किंटवॉल पोस्ट, 8650 नशीली गोлияयां/किन्सूल, 202 ग्राम आइस ड्रग और 01 किंटवॉल से ज्यादा गोला नष्ट किया। एस.एस.पी. फरीदकोट डॉ. प्रज्ञा जैन ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ड्रग्स की यह भारी मात्रा, जो 66 एन.डी.पी.एस. मामलों से जुड़ी है, आज पूरी पारदर्शिता के साथ नष्ट की गई है। उन्होंने कहा कि फरीदकोट पुलिस ड्रग्स को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार कमिंटमेंट के साथ काम कर रही है। जिसके तहत फरीदकोट पुलिस ने पिछले



कुछ सालों में एन.डी.पी.एस.एक्ट के तहत बड़ी मात्रा में ड्रग्स जवाब दिए हैं। जिसमें आज बरगद ड्रग्स को नष्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा ड्रग्स के खिलाफ युद्ध की गई मुहिम 'ड्रग्स के खिलाफ जंग' में पूरी तरह से असरदार साबित हुई है, जिसके दौरान मार्च 2025 से अब तक फरीदकोट पुलिस द्वारा 1089 केस दर्ज किए गए हैं और 1652 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पिछले 19 महीनों के दौरान संबद्ध अर्थाईटी से मंजूरी मिलने के बाद ड्रग तस्करी की 09 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी फ्रीज की गई है। इस दौरान डा. प्रज्ञा जैन ने जनता से अपील की कि वे ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और ड्रग तस्करी या सप्लायर्स के बारे में जानकारी शेयर करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा जारी सेफ पंजाब एंटी-ड्रग हेल्पलाइन नंबर 97791-00200 का इस्तेमाल करें, आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी।



इरान के साथ भारत के संबंध प्रभावित हुए हैं, जिसका परिणाम अब देश को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में आने वाली एलपीजी और तेल का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा हॉर्मुज जल दरारू मार्ग के माध्यम से आता है, जिस पर इरान कानियंत्रण है और अब इरान केवल उन देशों के जहाजों को ही वहां से गुजरने दे रहा है, जो गुट निरलेप हैं। लोकन वर्तमान समय में ईरान-इजराइल युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खुले तौर पर इजराइल व अमेरिका का साथ देने के कारण

देश में हाहाकार, गैस संकट का होटल/रेस्टोरेंट्स पर पड़ रहा सीधा असर

गया है, जिसका सीधा असर आम लोगों, होटल/रेस्टोरेंट्स कारोबारियों, वहां काम करने वाले लोगों और ग्राहकों पर पड़ रहा है। स. हरचंद सिंह बरसट ने कहा कि भारत की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह जवाब मांगती है कि एकतरफा विदेश नीति बनाते समय देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में क्यों नहीं सोचा गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि वे अमेरिका के दबाव के नीचे क्यों हैं और क्या वे अपने मित्र अडानी, जिस पर अमेरिका में केस दर्ज है, को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण वे भारत को बर्बाद करने वाली नीतियां बना रहे हैं। स. बरसट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दें, ताकि कोई दूरदर्शी और सूझवान प्रधानमंत्री भारत की विदेश नीति को संतुलित ढंग से बनाकर देश की अर्थव्यवस्था को तस्करी के रास्ते पर ले जा सके।

देश में हाहाकार, गैस संकट का होटल/रेस्टोरेंट्स पर पड़ रहा सीधा असर

प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़े प्रयासों के तहत 672 स्टाफ नर्सों की भर्ती की जाएगी

भगवंत मान सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को और मजबूत करने के लिए 672 स्टाफ नर्सों की भर्ती का ऐलान

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भगवंत मान सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए 672 स्टाफ नर्सों की भर्ती के लिए विज्ञापन सार्वजनिक कर दिया है। भर्ती से संबंधित यह विज्ञापन प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है, जिसमें योग्य उम्मीदवारों को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट के आधिकारिक आनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।

इन 672 स्टाफ नर्सों की भर्ती से स्वास्थ्य देखभाल स्टाफ को और मजबूती मिलेगी: डॉ. बलबीर सिंह

पंजाब सरकार ने सरकारी अस्पतालों में नर्सीयों की देखभाल को और बेहतर बनाने के लिए 672 नई स्टाफ नर्सों के पदों के साथ स्वास्थ्य देखभाल स्टाफ में महत्वपूर्ण वृद्धि की

ध्यान देने योग्य है कि 672 नर्सों की यह भर्ती विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर पर नर्सिंग कार्यबल को और मजबूत करेगी। इस कदम से मरीजों की देखभाल में सुधार होगा और सरकारी अस्पतालों में काम के बोझ को कम करने में सहायता मिलेगी। स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल को मजबूत करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए पंजाब

नेटवर्क का विस्तार करने के साथ-साथ माध्यमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को भी मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हर निवासी तक पहुंचाई जा सकें। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं में 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से मुफ्त दवाइयों और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाई गई है, जिससे मरीजों की देखभाल और उपचार के परिणामों को और बेहतर बनाया जा सका है।

पंजाब भर के परिवारों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज देकर वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है, जिससे नागरिकों को बिना किसी आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

संक्षिप्त-समाचार

डायसन के साथ बेडरूम को बनाएं बेहतरीन स्लीप सैक्यूअरी

लुधियाना। बेहतर और गुणवत्तापूर्ण नींद के प्रति बढ़ती जागरूकता के चलते अब लोग अपने बेडरूम को ह्यूस्लीप सैक्यूअरीइयानी आराम और गहरी नींद के लिए अनुकूल स्थान में बदलने लगे हैं। वर्ल्ड स्लीप डे के मोक़े पर, डायसन ने बेडरूम को एक हेल्टी स्लीप सैक्यूअरी बनाने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं। डायसन के अनुसार, बेडरूम अब केवल सोने का कमरा नहीं रहा, बल्कि इसे आराम और शरीर की रिकवरी के लिए खास तौर पर तैयार किया जाने लगा है। विशेषज्ञों के अनुसार, यही वातावरण वाला बेडरूम नींद की गुणवत्ता और समग्र स्वास्थ्य को काफी बेहतर बना सकता है। एक आदर्श स्लीप सैक्यूअरी केवल आरामदायक बिस्तर तक सीमित नहीं होती। इसमें इनडोर हवा की गुणवत्ता, गंदे की स्वच्छता, बिस्तर की सामग्री और कमरे की साफ-सफाई जैसे महत्वपूर्ण कारक शामिल होते हैं। साफ और स्वस्थ वातावरण एलर्जी, धूल और अन्य वायु प्रदूषकों को कम करने में मदद करता है, जो नींद को प्रभावित कर सकते हैं। डायसन के अनुसार, डायसन हशजेट प्यूरीफायर कॉम्पैक्ट जैसे उपकरण हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों को पकड़कर कमरे में शुद्ध हवा का संचार करते हैं। यह स्लीप मोड में केवल 24डीबीए की कम ध्वनि पर काम करता है, जिससे नींद में बाधा नहीं आती। विशेषज्ञ गहरी नींद के लिए सिफारिश की भी सलाह देते हैं, क्योंकि उनमें धूल और एलर्जी पैदा करने वाले कण जमा हो जाते हैं। इसके अलावा, कमरे में अनावश्यक सामान कम रखना, सोने से पहले तेज सुगंधित उत्पादों का उपयोग घटना और हर सुबह बिस्तर को थोड़ी देर खुला छोड़ना भी स्वस्थ और आरामदायक नींद के वातावरण बनाने में सहायक होता है।

सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज और गैलेक्सी बड्स4 सीरीज भारत में उपलब्ध

चंडीगढ़। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपनी नई गैलेक्सी S26 सीरीज और गैलेक्सी बड्स4 सीरीज की वैश्विक उपलब्धता की घोषणा कर दी है। सैमसंग की तीसरी पीढ़ी के एआई स्मार्टफोन्स के रूप में गैलेक्सी S26 अल्ट्रा, गैलेक्सी S26+ और गैलेक्सी S26 उपयोगकर्ताओं को अधिक सहज और स्मार्ट एआई अनुभव देने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे वे कम चरणों में अधिक काम कर सकते हैं। गैलेक्सी अनोपक ड्रैफ्ट के बाद से नई सीरीज को दुनियाभर में शानदार प्रतिक्रिया मिली है। शुरूआती प्री-ऑर्डर आंकड़ों में दबाई अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। इनमें गैलेक्सी S26 अल्ट्रा सबसे लोकप्रिय मॉडल बनकर उभरा है, जिसे वैश्विक स्तर पर 70 प्रतिशत से अधिक चाहकों ने चुना। गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में सैमसंग की कई उन्नत तकनीकों को एक साथ शामिल किया गया है। इसमें शक्तिशाली प्रदर्शन, इंस्ट्री-लीडिंग केमरा सिस्टम, बेहतर गैलेक्सी एआई अनुभव और दुनिया का पहला बिल्ट-इन प्रॉक्सेसिंग डिस्प्ले दिया गया है। यह प्रॉक्सेसिंग डिस्प्ले तकनीक में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो पिक्सल स्तर पर उपयोगकर्ता की गोपनीयता की सुरक्षा करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन इस तरह तैयार किया गया है कि रोजमर्रा के उपयोग में स्क्रीन की गुणवत्ता से समझौता किए बिना प्रॉक्सेसिंग सुरक्षित रहे।

एआई टूल्स के साथ वीवो वाई51 प्रो 5जी हुआ लॉन्च

चंडीगढ़। वीवो इंडिया ने अपने वाई सीरीज में नया स्मार्टफोन वीवो वाई 51 प्रो 5जी लॉन्च किया। नया वाई 51 प्रो 5जी उन यूजरों के लिए डिजाइन किया गया है जो स्मूथ और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के साथ ड्यूसीपिंट एंटरटेनमेंट चाहते हैं। यह स्मार्टफोन ऐसा अनुभव देता है जो रोजमर्रा की तेज और बदलती दिनचर्या के साथ कदम मिलाकर चलता है। लंबे समय तक चलने वाली परफॉर्मेंस, स्मूथ ह्यूटीएटिक्टिंग और रोजमर्रा के आसान इस्तेमाल पर खास ध्यान देते हुए यह डिवाइस वीवो की उस सोच को दिखाता है जिसमें वह ऐसे प्रैक्टिकल इन्वेंशंस लाना चाहता है जो प्रोडक्टिविटी और एंटरटेनमेंट दोनों में मदद करें और सीरीज के पोर्टफोलियो में लंबे समय तक वैल्यू दें। वीवो वाई 51 प्रो 5जी में शानदार डिजाइन दिया गया है, जिसमें सीमलेस वन-पीस फ्रेम और 3डी ग्लाड-कर्व बैक है, जो फोन को हाथ में पकड़ने पर आरामदायक बनाता है। बड़े रेडियस वाले कर्नल और मेटैलिक केमरा डेको के साथ प्रीमियम लुक देते हैं। यह दो रंगों में उपलब्ध है - फेस्टिव रेड, जो त्योहारों की लाइटन की गर्म रोशनी से प्रेरित है और ब्लैक बेजल के साथ आता है; और नोबल गोल्ड, जिसमें वीवो का सिग्नेचर ग्रेडिएंट ओटिंग डिजाइन है, जो 3डी डेथ इफेक्ट देता है।

आईसीसी की बड़ी कार्रवाई, वेस्टइंडीज के खिलाड़ी जेवोन सर्लर्स सहित तीन निलंबित

बिमा10 लीग पर फिक्सिंग का साया: जेवोन सर्लर्स और चित्तरंजन राठौड़ पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली/बारबाडोस
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने भ्रष्टाचार विरोधी नियमों के उल्लंघन के मामले में वेस्टइंडीज के खिलाड़ी जेवोन सर्लर्स, टीम अधिकारी ट्रेवोन ग्रिफिथ और टाइटंस टीम के मालिक चित्तरंजन राठौड़ पर आरोप लगाए हैं। यह मामला 2023-24 में बारबाडोस में आयोजित बिमा10 क्रिकेट टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ है।

जांच के बाद तीनों व्यक्ति पर क्रिकेट वेस्टइंडीज के भ्रष्टाचार विरोधी नियमों के तहत कई आरोप लगाए गए हैं। राठौड़ पर तीन, सर्लर्स पर चार और ग्रिफिथ पर चार आरोप लगाए गए हैं। इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने बिमा10 टूर्नामेंट के मैचों के परिणाम, प्रगति या अन्य पहलुओं को अनुचित तरीके से प्रभावित करने या ऐसा करने



की साजिश रचने का प्रयास किया। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित व्यक्तियों ने खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को भ्रष्टाचार विरोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए उकसाने या सहायता करने का प्रयास

किया। इसके अलावा तीनों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने संभावित भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच में सहयोग नहीं किया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। साथ ही सर्लर्स

और ग्रिफिथ पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने क्रिकेट वेस्टइंडीज को उन संघर्षों या प्रस्तावों की जानकारी नहीं दी, जिनका उद्देश्य खिलाड़ियों को भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल करना था।

ट्रेवोन ग्रिफिथ पर अतिरिक्त रूप से यह आरोप भी लगाया गया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़ी जांच के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने या उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इन आरोपों के बाद तीनों को तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के क्रिकेट से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने 11 मार्च 2026 से 14 दिनों के भीतर इन आरोपों का जवाब देने का समय दिया गया है।

यह मामला एक व्यापक जांच का हिस्सा है, जिसके तहत इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाड़ी एरॉन जोन्स पर भी भ्रष्टाचार विरोधी नियमों के उल्लंघन के कई आरोप लगाए जा चुके हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कहा है कि अनुशासनात्मक प्रक्रिया पूरी होने तक इस मामले में आगे कोई दिव्यणी नहीं की जाएगी।

चैंपियंस लीग: आर्सेनल और लेवरकुजेन के बीच खेला गया मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त

एजेंसी (हि.स.)
बर्लिन

चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के पहले मुकाबले में आर्सेनल और बायर लेवरकुजेन के बीच खेला गया मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। बिअरएरेना स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए इस मुकाबले में आर्सेनल को अंतिम मिनटों में पेनल्टी मिली, जिस पर काई हावर्स ने गोल कर टीम को हार से बचा लिया। मुकाबले की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने सावधानी के साथ खेल दिखाया और मजबूत रक्षण पर ध्यान दिया। लेवरकुजेन के कप्तान रॉबर्ट आद्रिख शुरुआती मिनटों में ही चर्चा में आ गए जब उन्होंने आर्सेनल के खिलाड़ी विक्टर योकेरिस को बॉक्स के बाहर रोक दिया, जिसके कारण उन्हें पीला कार्ड मिला।

आर्सेनल ने गेंद पर अधिक नियंत्रण रखा, लेकिन लेवरकुजेन की मजबूत रक्षा पंक्ति के कारण स्पष्ट अवसर कम ही बन सके। पहले हाफ के मध्य में गैब्रियल मार्तिनेली ने शानदार कर्लिंग शॉट लगाया, लेकिन गेंद ब्रॉक्सर से टकराकर बाहर चली गई। दूसरी ओर लेवरकुजेन की ओर से इब्राहिम माजा ने कुछ हमले किए, मगर पहले हाफ के



अंत तक कोई भी टीम गोल करने में सफल नहीं हो सकी। दूसरे हाफ की शुरुआत होते ही लेवरकुजेन ने बढ़त बना ली। मार्टिन टेरियर के हेडर को गोलकीपर डेविड राया ने शानदार तरीके से रोका, लेकिन इसके बाद मिले कॉर्नर पर एलेजांद्रो ग्रिमाल्डो की गेंद दूर पोस्ट तक पहुंची, जहां रॉबर्ट आद्रिख ने हेडर लगाकर गोल कर दिया। इस गोल के बाद लेवरकुजेन की टीम ने मजबूत रक्षण करते हुए आर्सेनल को ज्यादा मौके नहीं दिए। मुकाबले के अंतिम क्षणों में आर्सेनल को बड़ा मौका मिला। पेनल्टी क्षेत्र में मलिक टिलमैन ने नोनी माडुके को रोका, जिसके बाद

दबाव वाली परिस्थितियों में जिम्मेदारी लेना पसंद है: जसप्रीत बुमराह

एजेंसी (हि.स.)
अहमदाबाद

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टी20 विश्व कप में खिताब का बचाव करना अपने करियर के सबसे संतोषजनक अनुभवों में से एक करार देते हुए कहा कि उन्हें दबाव वाली परिस्थितियों में जिम्मेदारी लेना अच्छा लगता है। बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रिविचर को नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में चार विकेट लेकर भारत की 96 रन से जीत में अहम भूमिका निभाई। इससे भारत टी20 विश्व कप में अपने खिताब का बचाव करने और तीन बार यह ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बन गई।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें बुमराह ने कहा, मैं पंदे के पीछे नहीं रहना चाहता हूं। मैं हमेशा सक्रिय रूप से भाग लेना चाहता हूं। मुझे शुरू से ही चुनौतियां पसंद हैं। बुमराह को फाइनल में शानदार प्रदर्शन करने के



लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। उन्होंने कहा, मैंने क्रिकेट इसी मकसद से खेला है। मैंने क्रिकेट खेलना इसी मकसद से शुरू किया था। जब मैं कुछ बदलाव लाता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। इससे बेहतर कोई अहसास नहीं है। गुजरात में जन्में इस तेज गेंदबाज के लिए यह जीत भावनात्मक रूप से और भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह जीत उसी स्थान पर मिली जहां से उनके क्रिकेट करियर की शुरुआत हुई थी। बुमराह ने कहा, मैंने यहीं से क्रिकेट खेलना शुरू किया। मैंने अपना अधिकतर क्रिकेट यहीं खेला है। मैं यहीं गुजरात के लिए खेले हुए आगे बढ़ा। यहीं विश्व कप जीता और मैंन ऑफ द मैच बना।

बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कार समारोह में गिल का 'क्रिकेटर ऑफ द ईयर' चुना जाना तय

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल का 15 मार्च को यहां होने वाले बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) के वार्षिक पुरस्कार समारोह में 'क्रिकेटर ऑफ द ईयर' चुना जाना तय है। इस 26 वर्षीय खिलाड़ी को हाल में विश्व कप के खिताब का बचाव करने वाली टी20 टीम में नहीं चुना गया था, लेकिन उन्होंने अन्य दो प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन किया। गिल ने 2025 में टेस्ट मैचों में 70 से अधिक के औसत से 983 रन बनाए, जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ उसकी धरती पर ड्रॉ रही श्रृंखला में बनाए गए 754 रन भी शामिल हैं। गिल ने चैंपियंस ट्रॉफी वनडे टूर्नामेंट में भी भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 188 रन बनाए और इस तरह से वर्ष 2025 में वनडे में कुल 490 रन बनाए। गिल ने कुल मिलाकर तीनों प्रारूपों में 49 के औसत से 1,764 रन बनाए, जिसमें सात शतक और तीन



अर्धशतक शामिल हैं। हालांकि टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उनका प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं रहा, लेकिन आईपीएल में वह शानदार फॉर्म में थे। आईपीएल में उन्होंने गुजरात टाइटन्स की तरफ से खेलते हुए 50 की औसत से 650 रन बनाए। भारत के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड को भारतीय क्रिकेट में उनके अमूल्य योगदान के लिए कर्नल सिके नायडू 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड' से सम्मानित किया जाना तय है। उनके मुख्य कोच रहते हुए भारत ने 2024 में टी20 विश्व कप का खिताब जीता था। मुंबई क्रिकेट संघ (एम्ससीए) को घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ एसोसिएशन का पुरस्कार मिलने की संभावना है।

मन्नेपल्ली स्विस ओपन के दूसरे दौर में

बासेल। भारतीय शटलर धारुन मन्नेपल्ली ने जानाच के अपने प्रतिद्वंदी केटा निशिमोटो के निर्णायक सेट में रिटाचर होने के बाद स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल के दूसरे दौर में जगह बनाई। विश्व रैंकिंग में 43वें स्थान पर काबिज मन्नेपल्ली बुधवार की रात खेले गए इस मैच में तब 16-21 21-16 7-2 से आगे चल रहे थे, जब पांचवीं वरीयता प्राप्त निशिमोटो ने कंधे में दर्द के कारण मैच से हटने का फैसला किया। पिछले साल मकाऊ ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले 24 वर्षीय मन्नेपल्ली का अलावा मुकाबला मलेशिया के जस्टिन होह से होगा। इस बीच महिला एकल में मालविका बंसोड़ थाईलैंड की विश्व में चौथे नंबर की खिलाड़ी पोर्नपावी चोयुवोन से एकतरफा मुकाबले में 11-21, 15-21 से हार गई। थाईलैंड की खिलाड़ी के खिलाफ यह उनकी चौथी हार है। गुरुवार को सात्विकासाईराज रंकीरेड्डी और विराग शेथी की विश्व के चौथे नंबर के पुरुष युगल जोड़ी, किरण जॉर्ज तथा ध्रुव कपिला और तनीशा क्रांटो की भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे।

यूईएफए चैंपियंस लीग: फेडेरिको वाल्वर्डे की हैट्रिक से रियल मैड्रिड की शानदार जीत

एजेंसी (हि.स.)
मैड्रिड

यूईएफए चैंपियंस लीग 2025-26 के राउंड ऑफ 16 के पहले मुकाबले में रियल मैड्रिड ने मैनेचेस्टर सिटी को 3-0 से हराकर बड़ा कदम क्वार्टर फाइनल की ओर बढ़ा दिया। सैंटियागो बर्नार्बेउ स्टेडियम में खेले गए इस मैच में उरुवे के मिडफील्डर फेडेरिको वाल्वर्डे ने अपने करियर की पहली हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। मैच के 20वें मिनट में गोलकीपर थियो कोर्टुआ ने लंबी पास पर वाल्वर्डे दौड़े और से तेज दौड़ लगाते हुए आगे बढ़े और गोलकीपर जियानलुइजी डोनारम्मा को छकाकर गेंद को गोल में पहुंचा दिया। सात मिनट बाद विनीसियस जूनियर के शानदार पास पर वाल्वर्डे ने ऑफसाइड ट्रैप को तोड़ते हुए दूसरा गोल दाग दिया। इससे रियल मैड्रिड ने



मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। पहले हाफ के 42वें मिनट में रियल मैड्रिड ने तीसरा गोल किया। ब्राह्मि डियाज के बेहतरीन पास पर वाल्वर्डे ने गेंद को आगे उछालकर शानदार वॉली लगाई और अपनी हैट्रिक पूरी कर ली। इस गोल के साथ स्टेडियम में मौजूद दर्शक खुशी से झूम उठे। दूसरे हाफ में मैनेचेस्टर सिटी ने वापसी की कोशिश की। जेरोमी डोकू और एंटेडोन सेमैन्यो ने आक्रमण तेज किया, लेकिन रियल मैड्रिड के गोलकीपर कोर्टुआ ने

शानदार बचाव करते हुए टीम की बढ़त बरकरार रखी। इस दौरान रियल मैड्रिड को एक और गोल करने का मौका भी मिला

जब विनीसियस जूनियर को पेनल्टी मिली, लेकिन डोनारम्मा ने शानदार बचाव करते हुए गोल होने से रोक दिया। इस जीत के साथ रियल मैड्रिड ने मुकाबले में मजबूत बढ़त बना ली है। अब दूसरा मुकाबला अगले सप्ताह इंग्लैंड में खेला जाएगा, जहां मैनेचेस्टर सिटी को अगले दौर में पहुंचने के लिए वापसी करनी होगी। वाल्वर्डे ने मैच के बाद कहा कि यह उनके लिए बेहद खास दिन था और टीम की जीत से वह बेहद खुश है।

ग्लोबल वार्मिंग के साथ हेल्थ वार्मिंग, इतिहास में पहली बार CO2 का स्तर सबसे ज्यादा

CO2 का रिकॉर्ड स्तर सेहत पर संकट



शरीर को स्वस्थ रखने और सभी अंगों के ठीक तरीके से काम करते रहने के लिए जरूरी है कि ऑक्सीजन युक्त खून का संचार निरंतर होता रहे। इसके लिए हमारे फेफड़े 24 घंटे सातों दिनों लगातार काम करते रहते हैं। हालांकि जिस तरह से पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, इससे वायुमंडल में मौजूद गैसों का संतुलन भी प्रभावित हो रहा है। नतीजतन सेहत को लेकर चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। जीवन का बेसिक साईंस है- हम सांस के जरिए ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यही हमारे अस्तित्व का आधार है। हालांकि पिछले एक दशक में कई रिपोर्ट्स में चिंता जताई जाती रही है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) का स्तर बढ़ रहा है। ये स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक हैं। बढ़ता कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक जलवायु परिवर्तन को तो बढ़ावा देता ही है साथ ही इससे कई तरह के स्वास्थ्य जोखिम भी हो सकते हैं, जिसको लेकर सावधान रहने की जरूरत है। इसी से संबंधित एक हालिया रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता स्तर इंसानी खून में भी दिखाई देने लगा है।

वातावरण में बढ़ता कार्बन डाइऑक्साइड

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, इसान ऐसे माहौल में विकसित हुए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 200-300 पार्ट्स प्रति मिलियन थी। समय के साथ यह आंकड़ा 420 ppm से ऊपर पहुंच गया है, ये हमारी प्रजाति के इतिहास में किसी भी समय से ज्यादा है। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की अतिरिक्त मात्रा जलवायु परिवर्तन में योगदान दे रही है, पर क्या आप जानते हैं कि यह हमारे शरीर की केमिस्ट्री को भी बदल रहा है?

अध्ययन में पता चला

इस खतरनाक ट्रेंड को समझने के लिए विशेषज्ञों की टीम ने दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य डेटासेट में से पिछले दो दशकों की जानकारी का अध्ययन किया। इसके आधार पर जो बातें समझ आई हैं वो काफी डराने वाली हो सकती हैं।

खून के एसिडिक होने का खतरा

जब थोड़े समय के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, तो इससे खून ज्यादा एसिडिक हो सकता है और खून में बाइकार्बोनेट का स्तर थोड़ा बढ़ जाता है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो किडनी पेशाब के जरिए निकलने वाले बाइकार्बोनेट की मात्रा को कम कर देती है और ज्यादा बाइकार्बोनेट बनाती है। इसका कुल असर यह होता है कि खून में बाइकार्बोनेट का स्तर बढ़ जाता है, जिससे लगातार बनी रहने वाली एसिडिक स्थिति से का मुकाबला किया जा सके।

सेहत पर क्या हो सकता है इसका असर

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, इस अध्ययन का यह मतलब ये नहीं है कि जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाएगा, तो लोग अचानक बीमार पड़ने लगेंगे। हालांकि डेटा से जो संकेत मिल रहा है, वह ध्यान देने लायक है। CO2 का बढ़ता स्तर ब्लड केमिस्ट्री में धीरे-धीरे बदलाव ला रही है। हमें वातावरण को बनावट पर भी पारंपरिक जलवायु संकेतकों के साथ-साथ नजर रखी जानी चाहिए। यह लंबे समय में लोगों को सेहत पर असर डालने वाला एक संभावित कारक हो सकता है।

हाइपरकार्बिया का असर

खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने को हाइपरकेमिनिया या हाइपरकार्बिया कहते हैं। इसकी वजह से रिसिप्टरी एसिडोसिस हो जाता है, जिससे खून बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। इसके लक्षणों में तेज सिरदर्द, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आने, भ्रम, पैनिनक अटैक जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। गंभीर मामलों में अगर इलाज न किया जाए तो मरीज कोमा में भी जा सकता है या उसकी मौत भी हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से दिमाग की नसें फैल (सेरेब्रल वैडोइडालेशन) जाती हैं, जिससे दिमाग में खून का दबाव बढ़ जाता है। इसकी वजह से तेज सिरदर्द और चक्कर आने लगते हैं।

दर्पण

शुगर-बीपी नहीं रहता कंट्रोल तो किडनी से भी धो बैठेंगे हाथ

किडनी हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। भले ही ये अंग काफी छोटा सा होता है, लेकिन शरीर के कामकाज में इसकी बड़ी भूमिका होती है। किडनी रोजाना लगभग 130-140 लीटर खून को छानकर उसमें से जहरीले पदार्थ, अपशिष्ट जैसे यूरिया-क्रिएटिन और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालती है। किडनी की ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स (सोडियम, पोटेशियम) का संतुलन बनाए रखने, रक्त के pH स्तर को नियंत्रित करने जैसे इस छोटे से अंग के कई बड़े-बड़े काम हैं। हालांकि दुनिया भर में किडनी से संबंधित बीमारियों के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कम उम्र के लोगों में भी इसका खतरा देखा जा रहा है। किडनी की समस्याओं पर अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो इससे किडनी फेलियर तक का खतरा रहता है जिसे जानलेवा माना जाता है। किडनी की बीमारियों के लिए लाइफस्टाइल-खानपान में गड़बड़ी को प्रमुख माना जाता है।

हाई शुगर के कारण किडनी की बीमारी

डॉक्टर कहते हैं, जिन लोगों का शुगर लेवल अक्सर बढ़ा हुआ रहता है उनमें किडनी की बीमारियों का खतरा अधिक हो सकता है। लंबे समय तक हाई शुगर की समस्या किडनी की छोटी-छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। इससे डायबिटिक नेफ्रोपैथी की समस्या हो सकती है। लगातार हाई ग्लूकोज के कारण फिल्टरिंग सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे पेशाब में प्रोटीन जाने लगता है, इससे क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकती है।

हाई ब्लड प्रेशर कितना खतरनाक

हाई ब्लड शुगर की ही तरह से ब्लड प्रेशर भी रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव डालता है। ब्लड प्रेशर के कारण किडनी की नाजुक नसें धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त होने लग जाती हैं। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो शरीर में नमक और पानी जमा होने लगता है, जिससे बीपी और बढ़ा रहता है। जिन लोगों को हाई बीपी और हाई शुगर दोनों समस्याएं हैं, उनमें किडनी की बीमारी और इसके खराब होने का खतरा और भी ज्यादा होता है।

किडनी को हेल्दी रखने के लिए क्या करें

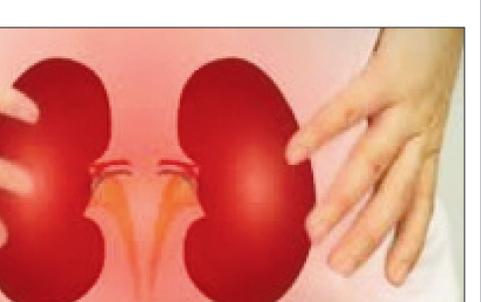
किडनी रोग विशेषज्ञ बताते हैं, बीपी और शुगर के मरीजों को किडनी की सेहत को लेकर खास सावधानी बरतनी रहना चाहिए। इन दोनों को कंट्रोल में रखकर आप बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल में सुधार करना भी जरूरी है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम करें। इससे ब्लड प्रेशर, वजन और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए एक वजन से कम नमक का सेवन करें। किडनी को शरीर से गंदगी निकालने में मदद करने के लिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें। आहार में तजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज की मात्रा बढ़ाएं। प्रोसेस्ड, ज्यादा सोडियम वाले और मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन कम या बिल्कुल न करें। वजन को कंट्रोल रखें। मोटापा की स्थिति डायबिटीज, हाइपरटेंशन और किडनी की बीमारियों को बढ़ाने वाली हो सकती है। धूम्रपान करने से किडनी में रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है, इसलिए धूम्रपान न करें।

डाइट प्लान

शोध से पता चलता है कि डाइट का पालन करने से क्रॉनिक किडनी डिजीज (सीकीडी) होने का जोखिम कम हो जाता है। जिन लोगों को पहले से ही सीकीडी है उनमें भी इससे विशेष लाभ देखे गए हैं। इसमें डरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, फलियां, मेवे और अनसेचुरेटेड तेल का सेवन ज्यादा करने की सलाह दी जाती है। मछली, मुर्गी, अंडे और डेयरी उत्पादों का सेवन कम करना होता है। डाइट में रेड मीट, चीनी, रिफाईंड अनाज और सेचुरेटेड फैट वाली चीजों को न खाने की सलाह दी जाती है। खान-पान के इस तरीके को किडनी को हेल्दी रखने और सीकीडी के जोखिम को कम करने में मदद करने वाला पाया गया है। इसमें पौधों से भरपूर मात्रा में प्रोटीन लेने पर जोर दिया जाता है, ये जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन की तुलना में ज्यादा फायदेमंद होता है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी पोषक तत्वों की ज्यादा मात्रा किडनी के उत्तकों को नुकसान से बचाने और सूजन को कम करने में मदद करती है। यह डाइट सीकीडी के जोखिम कारकों, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मोटापे को नियंत्रित करने में मदद करती है। इस डाइट के माध्यम से भरपूर फाइबर लेने से पेट के माइक्रोबायोम में सुधार होता है, जिससे उच्च यूरेमिक टॉक्सिन का उत्पादन कम हो जाता है जो किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर दुनिया भर में डाइट के इस पैटर्न को अपनाया जाए तो समय से पहले होने वाली लाखों मौतों को रोका जा सकता है। इस डाइट में संतुलित मात्रा में प्रोटीन, हेल्दी फैट और कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं। यह डाइट ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को भी नियंत्रित रखने में मदद करती है। वृद्धि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर सीकीडी के मुख्य कारण हैं, इसलिए इन कारकों को नियंत्रित करना किडनी को होने वाले जोखिमों से बचाने में मदद करती है।

किडनी का कैंसर सिर्फ बुजुर्गों को होता है

दुनिया भर में बढ़ती किडनी की बीमारियों को लेकर लोगों को शिक्षित और जागरूक करने और किडनी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर अचेत करने के उद्देश्य से हर साल मार्च महीने के दूसरे गुरुवार (इस बार 12 मार्च) को विश्व किडनी दिवस मनाया



जाता है। यह सही है कि किडनी के कैंसर का खतरा बुजुर्गों में अधिक देखा जाता रहा है पर हालांकि यह कम उम्र वालों को भी हो सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि युवा आबादी में 50 से कम आयु वाले एक तिहाई लोगों में इसका खतरा हो सकता है। खराब जीवनशैली और अल्कोहल की आदत, कैंसर की फिमिली हिस्ट्री या फिर किडनी की पहले से ही रही कुछ बीमारियों के कारण युवा भी इसके शिकार हो सकते हैं।

अल्कोहल से नहीं होता किडनी कैंसर

स्वास्थ्य विशेषज्ञ, किडनी और लिवर दोनों के लिए अल्कोहल को खतरनाक मानते हैं। शराब का सेवन करने से पूरे शरीर पर इसके गंभीर दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। अल्कोहल की ही तरह धूम्रपान भी किडनी कैंसर के विकास के जोखिम को दोगुना कर देता है। सिर्फ यही दो आदतें पुरुषों में किडनी में कैंसर के लगभग 30% और महिलाओं में लगभग 25% का कारण बनती हैं।

किडनी कैंसर का खतरा महिलाओं में अधिक

किडनी का कैंसर किसी भी उम्र या लिंग वालों को हो सकता है। हालांकि पुरुषों में महिलाओं की तुलना में इसका जोखिम लगभग दोगुना होता है। धूम्रपान और कार्यस्थल पर कैंसर पैदा करने वाले विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने के कारण इसका खतरा अधिक हो सकता है। जिन महिलाओं को बार-बार यूटीआई या यौनि संक्रमण होता रहता है उन्हें डॉक्टर से मिलकर किडनी की सेहत की जांच जरूर कराते रहना चाहिए।

किडनी में स्टोन की समस्या

किडनी में स्टोन की समस्या काफी आम है। बच्चे ही या बुजुर्ग, महिला या पुरुष सभी में ये दिक्कत देखी जा रही है। खान-पान और लाइफस्टाइल में गड़बड़ी को इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है। आपको अभी किडनी में स्टोन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी ये दिक्कत नहीं होगी। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को निरंतर किडनी में पथरी होने से बचाव के लिए जरूरी उपाय करते रहने की सलाह देते हैं।

